A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 8 नवंबर, 2024

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-69 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को कैसे मात दे गए मिस्टर डोनाल्ड ?

दीपांशु मोहन, अंकुर सिंह आर्यन, गोपालकृष्णन

डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है। ट्रंप की यह जीत अमेरिका में चल रही आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच रूढ़िवादी प्राथमिकताओं की ओर बदलाव का प्रतीक है।

अमेरिका में जैसे रात होती गई, चुनावी रूप से महत्वपूर्ण कुछ स्विंग स्टेट्स ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। फ्लोरिडा ने ट्रंप को शुरुआत में ही जीत का गुलदस्ता थमाया और यहां से उन्होंने अपनी निर्णायक जीत में 30 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। दोनों पार्टियों के बीच झूलते रहने के इतिहास के साथ अपनी जनसांख्यिकीय विविधता के लिए जाना जाने वाला फ्लोरिडा, ट्रंप के चुनावी अभियान के लिए एक ऐसा राज्य था, जो उन्हें कुर्सी पाने के लिए जीतना ही था। यहां ट्रंप की सफलता ने उनके आर्थिक संदेश की स्वीकृति पर मुहर लगाई है, जहां कई लोग महंगाई और बढ़ती जीवन लागत का दबाव महसूस कर रहे हैं। इसके बाद यह चुनावी रेस एरिजोना में शिफ्ट हो गई, जहां सीमा सुरक्षा पर ट्रंप का दृढ़ स्टैंड वोटरों के एक बड़े हिस्से को आकर्षित करता रहा। इमिग्रेशन से जुड़े जटिल मुद्दों वाले सीमावर्ती राज्य एरिजोना में कई वोटर ट्रंप के कट्टरपंथी नजरिए से जुड़ते दिखे।

इस बीच, जॉर्जिया में जनसांख्यिकीय बदलावों के बीच भी ट्रंप का प्रभाव मजबूत बना रहा। नॉर्थ कैरोलिना ने अपने 16 इलेक्टोरल वोट ट्रंप के खाते में जोड़ दिए, जिससे पूरे दक्षिणी अमेरिका में उनका समर्थन बढ़ गया और पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी क्षेत्र पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। लेकिन सबकी नजर पेन्सिलवेनिया के इर्द-गिर्द जमी थी, जहां के 19 इलेक्टोरल वोट राष्ट्रपति की कुर्सी के रेस में बड़े अहम हैं। मजदूर वर्ग के आधार और अलग-अलग समुदायों के वोटरों के लिए जाना जाने वाला पेन्सिलवेनिया एक कड़े मुकाबले का मैदान बन गया। यहां कमला और ट्रंप, दोनों खेमे इसके समर्थन के लिए जोर-शोर से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आखिर में ट्रंप ने इसे भी जीत लिया।

जहा स्विंग स्टेट्स ने सुर्खियां बटोरीं, वहीं ट्रंप की व्यापक अपील जनसांख्यिकी और उन क्षेत्रों तक पहुंची जो आम तौर पर रूढ़िवादी उम्मीदवारों के साथ नहीं जाते थे। इसने ट्रंप के मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया। ट्रंप के चुनावी कैंपेन की बदौलत युवा वोटरों, ग्रामीण समुदायों और यहां तक कि कुछ हिस्पैनिक और ब्लैक वोटर समूहों के बीच उन्हें बढ़त मिलता दिखी। इन वोटों को अक्सर मान लिया जाता है कि इनका झुकाव तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ही होगा।

युवा वोटरों के बीच ट्रंप को सफलता क्यों मिली, खासतौर पर टेक्सास, ओहियो जैसे राज्यों और यहां तक कि कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली के कुछ हिस्सों में? दरअसल इसकी वजह है कि ट्रंप ने उनकी गंभीर चिंताओं को संबोधित किया, जैसे आर्थिक सुरक्षा, नौकरी की संभावनाएं और महंगाई। वहीं कमला हैरिस ने शहरी केंद्रों में कई युवा वोटरों को आकर्षित किया, पूर्व राष्ट्रपति के आर्थिक सुधार के वादे छोटे शहरों और उपनगरीय क्षेत्रों में गूंजते रहे, जहां तत्काल वित्तीय मुद्दों ने सामाजिक मुद्दों को मात दे दी है।

इंडियाना, केंटकी और टेनेसी जैसी जगहों पर भी ग्रामीण वोटरों की वोटिंग में बढ़ोतरी हुई। ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिरता, पारंपरिक मूल्यों और पुनर्जीवित कृषि क्षेत्र पर ट्रंप के फोकस ने कई ग्रामीण वोटरों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया है। जबकि इन्होंने पिछले चुनावों में भाग नहीं लिया था। ट्रंप के सीधे दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर जोर ने इन समुदायों के साथ जुड़ाव पैदा किया होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग हुई।

जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेन्सिलवेनिया में 2020 और 2024 में हुई वोटिंग की तुलना- अप्रत्याशित रूप से, ट्रंप को हिस्पैनिक और ब्लैक वोटरों के वोटिंग पैटर्न में शिफ्ट से मदद मिली, खासकर आर्थिक चुनौतियों से प्रभावित क्षेत्रों में। न्यू मैक्सिको और अलबामा जैसी जगहों पर, सामुदायिक सुरक्षा और रोजगार सृजन के बारे में ट्रंप के मैसेज ने लोकप्रियता हासिल की। युवा, ग्रामीण और अल्पसंख्यक वोटरों के गठजोड़ ने ट्रंप को उन क्षेत्रों में पकड़ हासिल करने में मदद की, जिनकी चुनावी पंडितों को उम्मीद नहीं थी। कमला हैरिस के लिए यह रास्ता किसी कठिन चढ़ाई से कम नहीं रहा। चुनावी दौड़ की शुरुआत में, उनकी टीम ने नेवादा और मिशिगन जैसे राज्यों में मामूली बढ़त बनाए रखने पर बहुत ध्यान केंद्रित किया, जबकि युवा और शहरी वोटरों के बीच उच्च मतदान कराने के लिए काम किया। युवा मतदाताओं के बीच शुरूआती मजबूती दिखने के बावजूद, कमला हैरिस के हाथ से पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बढ़त फिसल गई। नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन जैसे राज्यों में, हार निर्णायक मोड़ साबित हुई। ट्रंप की जीत अमेरिकी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, जो नए सिरे से रूढ़िवादी ऊर्जा और प्राथमिकताओं से प्रेरित होगी।

2024 में ट्रंप की जीत भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। उनके 'अमेरिका फर्स्ट' दृष्टिकोण से वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ने और बाजार की गतिशीलता प्रभावित होने की संभावना है। हाई टैरिफ और संभावित रूप से अंतरराष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका के पीछे हटने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, खासकर अगर चीन के साथ तनाव बढ़ता है। आपूर्ति श्रृंखला में इस बदलाव से उत्पादन लागत बढ़ सकती है, आर्थिक विकास धीमा हो सकता है और तकनीक और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में श्रम (लेबर) की कमी पैदा हो सकती है, जो कुशल विदेशी श्रमिकों पर निर्भर हैं। यदि ट्रंप एच-1बी वीजा पर सीमा सहित इमिग्रेशन प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हैं, तो भारत के आईटी और तकनीकी उद्योग संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि वे काफी हद तक कुशल श्रमिकों पर निर्भर हैं जिनकी अमेरिका तक पहुंच है।

हालांकि इसके साथ भारत को इन चुनौतियों में रणनीतिक अवसर मिल सकते हैं। जैसा कि ट्रंप चीन से अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की चाहत रखने वाली अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है, अनुकूल नीतियों के साथ खुद को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। यह बात सही है कि आईटी सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे निर्यातों को प्रभावित करने वाले टैरिफ के कारण अमेरिका के साथ व्यापार में तनाव देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने से लाभ मिल सकता है।

इंडो-पैसिफिक में चीन का मुकाबला करने का साझा लक्ष्य हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की संभावना के साथ मजबूत सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। भारत अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार और रक्षा में इन बदलावों का लाभ उठा सकता है।

(दि क्विंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

लाड़ली बहना योजना

1.29 करोड़ बहनों को मिलेगी 1250 रूपये की नवम्बर माह की किश्त

- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 नवम्बर को इंदौर से करेंगे 1574 करोड़ रूपये अंतरित**

भोपाल (नप्र)। प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1250 रूपये की नवम्बर माह की किश्त जल्द मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 नवम्बर को इंदौर से 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 17 किश्तों का अंतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल 2 बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रूपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। योजना के प्रारंभ में पात्र हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान किया गया। अक्टूबर 2023 से मासिक आर्थिक सहायता की राशि में 250 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 का संचालन किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 18 हजार 984 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

योजना का प्रभाव

लाड़ली बहना योजना प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में शामिल है। योजना के वृहद स्वरूप ने प्रदेश की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में महती भूमिका निभाई है। इस योजना से न केवल महिलाओं ने अपनी छोटी-छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया है बल्कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से सीधे परिचित हुई हैं। इससे परिवार के निर्णयों में भी उनकी भूमिका बड़ी है और सामाजिक रूप से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है।

विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लक्ष्य को समर्पित है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि बौद्धिक एवं शारीरिक सामर्थ्य को अभिवर्धित कर विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवाभाव, सहनशीलता, समर्पण और त्याग की भावना जागृत कराने वाला भारत स्काउट्स गाइड्स संगठन, राष्ट्रीय व मानवीय मूल्यों को संचारित कर विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लक्ष्य को समर्पित है। संगठन का उद्देश्य सराहनीय है, यह प्रयास सतत् सफल हो, यही शुभेच्छा है।

पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर बीजेपी में शामिल

बुधनी में शिवराज सिंह के सामने घर वापसी; डेढ़ साल पहले कांग्रेस में गए थे

भोपाल (नप्र)। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में भाजपा की सदस्यता ली है। बता दें विधानसभा चुनाव के पहले दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर खातेगांव सीट से चुनाव लड़ा था। जिसमें वे 12542 वोटों से हार गए थे।

8 महीने पहले टल गई थी दीपक जोशी की भाजपा वापसी- 8 महीने पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर से भाजपा जॉइन करने वाले थे। उनका भोपाल के बीजेपी दफ्तर आकर घर वापसी का कार्यक्रम लगभग तय हो गया था। लेकिन आखिरी समय में ये कार्यक्रम टल गया था। दरअसल उस समय दीपक जोशी की भाजपा में वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। उस समय दीपक जोशी ने खुद मीडिया से चर्चा में कहा था - मैं तो सुबह का भूला हूं, शाम को घर लौट रहा हूं। 6 मई 2023 को पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। वे अपने पिता और पूर्व सीएम कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे। 6 मई 2023 को पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। वे अपने पिता और पूर्व सीएम कैलाश जोशी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे।

सुप्रभात

वह बहुत दिनों से प्रेम नहीं कर पा रही थी
मैं बहुत दिनों से झगड़ नहीं पा रहा था
मैं बहुत दिनों से प्रेम करना चाहता था
वह बहुत दिनों से झगड़ना चाहती थी
इन दिनों हमारे लिए सबकी कमी का
रोज़ ध्यान आता था
आकांक्षाएँ हमारे चाहने पर भी नहीं मिलती थीं।
हम इतने शिथिल और सुस्त थे कि
थामे हुए एक कमज़ोर धागे को, देखते
अपने–अपने सिर पर बचे, झूलते खड़े थे।
दिनों–दिन बड़े होते शहर
और छोटे होते घर में
न रोते, न हँसते
आँखें खोले
सुबह के स्वप्न की तरह थे दुनिया को देखते।

- नवल शुक्ल

2036 ओलंपिक

भारत को मिल सकती है मेजबानी

गुजरात बना प्रबल दावेदार, रिंग ऑफ यूनिटी बनेगी, जहां योग-गरबा कर सकेंगे

नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ का संभव

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारत ने ओलिंपिक-2036 के लिए अपनी दावेदारी दर्ज करा दी है। भारतीय ओलिंपिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक परिषद को पत्र लिखा है। अगर भारत की दावेदारी सफल रही तो गुजरात के अहमदाबाद को 2036 ओलिंपिक की मेजबानी मिल जाएगी। यह ऐतिहासिक मौका होगा, क्योंकि भारत पहली बार ओलिंपिक की मेजबानी करेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। ओलिंपिक 2036 के लिए 4600 करोड़ की लागत से 215 एकड़ में सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बनाया जा रहा है, जो ओलिंपिक का मुख्य फोकस पॉइंट होगा। गुजरात सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग 2036 की जरूरतों और लोगों की क्षमता को देखते हुए ही की गई है। अंतरराष्ट्रीय और पर्यावरणीय मानकों की भी स्टडी की गई है। साल 2036 में होने वाले ओलिंपिक के लिए 6,000 से 10,000 लोगों की कैपेसिटी वाला मल्टीपर्पज एरेना तैयार किया जाएगा।

जेट एयरवेज के फिर से शुरू होने की हर संभावना खत्म

- **सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन की सभी संपत्तियों को बेचने का दिया आदेश, 2019 से बंद है एयरलाइन**

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एनसीएलएटी का फैसला शीर्ष अदालत के जनवरी 2023 के फैसले की घोर अवहेलना है। कोर्ट के मुताबिक एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के रेजॉल्यूशन एप्लिकेंट जालान-कालरॉक कंसोर्टियम की 150 करोड़ रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी के समायोजन की अनुमति देकर न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश की अवहेलना की है। समाधान प्रस्ताव के मुताबिक एयरलाइन में 350 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत थी।

एनसीएलएटी ने परफॉरमेंस बैंक गारंटी को इसके अगेंस्ट एडजस्ट करने की अनुमति दी थी। नरेश गोयल के नेतृत्व वाली एयरलाइन कभी भारत की प्रमुख एयरलाइन थी लेकिन 2019 से ही इसका परिचालन बंद है। एनसीएलएटी ने जेट का मालिकाना हक यूके की कंपनी कालरॉक कैपिटल के पास है।

पूरी दुनिया मोदी को प्यार करती है, भारत एक अद्भुत देश

- **जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी से बोले ट्रंप**

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर फिर से बधाई दी। सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। उन्होंने भारत को एक महान देश और पीएम मोदी को एक महान नेता बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक सच्चा मित्र माना और कहा कि पीएम मोदी उनके चुनावी जीत के बाद सबसे पहले संपर्क करने वाले विश्व नेताओं में से एक हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 30 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 8 नवंबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

सलमान के बाद शाहरुख को जान से मारने की धमकी

- रायपुर से फैजान का आया फोन कॉल, मुंबई पुलिस छत्तीसगढ़ रवाना

मुंबई (एजेंसी)। सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बीच अब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली है। बांद्रा थाने में धमकी को लेकर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि रायपुर के रहने वाले फैजान नाम के शख्स ने दी धमकी दी है। शाहरुख खान को धमकी भरा फोन आया और उन्हें जान से मारने की बात कही गई। इस मामले के तुरंत बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मुंबई पुलिस जांच के

लिए रायपुर पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने फोन करने वाले का नाम पता ट्रेस कर लिया है। पुलिस जांच में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। नंबर ट्रेस करने पर रायपुर का पता मिला है। पुलिस यह भी छानबीन कर रही है कि ये शरारती तत्वों काम है या फिर फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। कहा जा रहा है कि इस घटना के बारे में रायपुर पुलिस को पहले ही मुंबई पुलिस इत्तेलाह कर चुकी है। हालांकि, वहीं रायपुर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह की तरफ से कहा गया है कि मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें वहां से किसी तरह के फोन कॉल की जानकारी अभी नहीं दी गई है। बता दें कि अब पुलिस फैजान को रिमांड पर लेकर मुंबई लेकर आएगी।

देश के दस बड़े लैबों में हो रही 'फंगस' की जांच

एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई थी 10 हाथियों की मौत

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत एक विशेष प्रकार के कवक (फंगस) के कारण हुई है। जांच रिपोर्ट में यह साफ है कि हाथियों की मौत इसी फंगस से हुई है लेकिन इस फंगस की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। यही मध्य प्रदेश वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अधिकारी इस मामले की जांच के लिए

देश की 10 बड़ी प्रयोगशालाओं, जिनमें हैदराबाद का लैब भी शामिल है, से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह तो साफ है कि कवक से निकलने वाले जहर ने इन हाथियों को मार डाला, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि यह किस प्रकार का फंगस है। दूसरे राज्य जहां सैकड़ों हाथी हैं, वे भी इन रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि कोदो फसल, खासकर उसके फंगस में विषाक्त पदार्थों के कारण हाथियों की मौत हुई है।

सिगरेट बनी उज्जैन के युवक की मौत का कारण

पीट-पीट कर हत्या की, लाश कुएं में फेंकी; दुर्लभ गैंग को फॉलो करता था मृतक

रतलाम (नप्र)। रतलाम के परवलिया बांछड़ा डेरे में मृत मिले युवक के मामले में गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। युवक की बांछड़ा डेरे में 10 रुपए की सिगरेट के 15 रुपए में लेने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद दुकानदार और उसके साथियों ने युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी बाइक से कुएं के पास पहुंचे और उसमें फेंक दिया। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि रतलाम के परवलिया बांछड़ा डेरे में उज्जैन के जिस युवक की हत्या हुई, वह उज्जैन के दुर्लभ गैंग को फॉलो करता था। उसके साथ आए सभी साथी भी दुर्लभ गैंग को अपना आइडिल मानते थे। रहते भी गैंग के सदस्यों की तरह ही थे। सभी के चेहरे और आंख के ऊपर गैंग के सदस्यों की तरह कट के निशान भी है। सभी उज्जैन के चाकूबाज थे।

1 नवंबर को साथियों के साथ उज्जैन से निकला था- बता दें कि रतलाम जिले के परवलिया गांव से लापता उज्जैन निवासी लोकेश (23) पिता भंवरलाल तंबोलिया का शव बुधवार दोपहर परवलिया के एक कुएं में मिला था। लोकेश अपने दोस्त आनंद उर्फ अभिषेक, सोमिक सुनहरे, रोहित कुमार, लखन, गोलू, गट्टू, कार्तिक और सौरभ के साथ उज्जैन से सांवलियाजी जाने के लिए 1 नवंबर को निकला था। उसी रात सभी रतलाम जिले के जावरा-नीमच फोरलेन स्थित बांछड़ा डेरे पर रुके थे।

लोकेश अपने एक साथी के साथ परवलिया रोड पर स्थित किराना दुकान पहुंचा। दुकानदार यक चौहान ने 10 रुपए की सिगरेट के 15 रुपए लिए। अधिक रुपए लेने पर आपत्ति जताते हुआ लोकेश ने दुकानदार को चाकू दिखाया। इसके बाद सभी दोस्त आए और ढाबे पर खाना खाने चले गए। ढाबे से लोकेश और सभी दोस्त खाना खाकर बाहर निकले तो वहां किराना दुकानदार यश और उसके साथी बाहर खड़े थे। दोनों के बीच चाकू दिखाने की बात पर विवाद हुआ। दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोकेश को पीटना शुरू कर दिया।

सभी जान बचा कर भागे

एसपी के मुताबिक मारपीट के बाद लोकेश समेत सभी दोस्त अपनी जान बचाकर इधर-उधर भाग गए। इसी दौरान लोकेश आरोपियों के हाथ लग गया, बाकी सभी दोस्त भाग गए। लोकेश को इतना मारा की उसकी मौत हो गई। जिसके बाद में उसे गांव के सरफराज के कुएं में फेंक दिया।

उज्जैन नहीं पहुंचा तो पता चला

अगले दिन तक जब लोकेश तंबोलिया घर नहीं पहुंचा। तब उज्जैन में सभी दोस्त मिले। पता चला कि लोकेश अभी तक घर नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। तब दोस्तों ने लोकेश के घरवालों को घटनाक्रम बताया। तब लोकेश के भाई के साथ दोस्त सोमिक सुनहरे उज्जैन से वापस आकर रतलाम जिले की ढोढर पुलिस चौकी पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया।

संदिग्धों को उठाया

एसपी अमित कुमार को घटनाक्रम के बारे में बता चला तो वह परवलिया पहुंचे। उसके बाद ग्राम परवलिया निवासी यश, रिंकू, पीयूष समेत 6 लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज लोकेश की तलाश शुरू की। वहीं, लापता युवक के मामले में लापरवाही के चलते ढोढर पुलिस चौकी प्रभारी कन्हैया अवश्या को भी संस्पेंड कर दिया।

पीएम मोदी के जीरो टॉलरेंस नारे को दुनिया ने अपनाया

शाह बोले-आतंकवाद के खिलाफ देश में मजबूत इकोसिस्टम बना

- आतंकियों की उम्र पहले से घटी, उठाए गए कई सख्त कदम

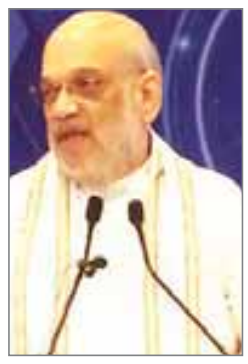

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दो -दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024 का इनॉगरेशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए है।

इससे आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नारे को केवल भारत ने ही नहीं पूरी दुनिया ने अपनाया है। अमित शाह ने आगे कहा कि ये सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ाएगा। दिल्ली में चल रहे नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी के इस सम्मेलन में पिछले कुछ सालों से आतंकवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई में आई समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीनियर पुलिस अधिकारी, स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी, फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल होंगे। शहीदों के परिवारों को धन्यवाद दिया सम्मेलन में संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल बीत चुके हैं।

एनएलआईयू-आईआईटी के बीच साइबर सेफ्टी पर जॉइंट डिग्री समझौता

भोपाल (नप्र)। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू, भोपाल) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी, इंदौर) साइबर सेफ्टी और साइबर लॉ में जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इस प्रोग्राम में एनएलआईयू, भोपाल और आईआईटी, इंदौर दोनों के फैकल्टी मेंबर एजुकेशन लेंगे। एनएलआईयू, भोपाल की ओर से कुलपति प्रोफेसर डॉ. एस. सूर्य प्रकाश और आईआईटी, इंदौर की ओर से निदेशक प्रोफेसर डॉ. सुहाश जोशी ने एमओयू (समझौता ज्ञापन) साइन किया है। अतुल कुमार पांडे, डीन, अंडरग्रेजुएट स्टडीज, प्रोफेसर देवेंद्र देशमुख, डीन-आउटरीच, आईआईटी इंदौर, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष बहुगुणा और रोहित शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, एनएलआईयू भी समारोह में शामिल हुए।

पेशेवरों को तकनीकी और कानूनी क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ाना मकसद

दो साल का कोर्स

मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम का मकसद उन कार्यरत पेशेवरों को एटवांस्ड ट्रेनिंग प्रदान करना है, जो तकनीकी और कानूनी क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाना चाहते हैं। कोर्स को तिमाही आधार (ट्राइसेमेस्टर) पर संचालित किया जाएगा। यह एक हाइब्रिड मोड में होगा, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास होंगी।

सीएम बनना मेरा टारगेट नहीं महायुति की जीत ज्यादा जरूरी

- चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा-मुख्यमंत्री पद के लिए कोई होड़ नहीं

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि महायुती में सीएम पद के लिए कोई लॉबिंग नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि महायुति की प्राथमिकता सत्ता में वापसी है। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पद के लिए कोई होड़ नहीं है। मुख्यमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में महायुति को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन सीएम शिंदे को अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर देने से सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए चुनाव जीतने की उम्मीद है। शिंदे की शिवसेना 288 सीटों में से 85 पर चुनाव लड़ रही है।

'महारानी' की आहट से सियासी गलियारों में मच गई हलचल

उपचुनाव में प्रचार से फिर दिखेगा वसुंधरा राजे का जलवा!

झुंझुनू के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में होगी सभा

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान होंगे। इसको लेकर सियासत में जमकर उठा पटक देखने को मिल रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर राजस्थान की सियासत में ऐक्टिव मूड में दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे झुंझुनूं विधानसभा सीट पर अपने प्रचार का जलवा दिखा सकती हैं। इसको लेकर बीजेपी में अंदर खाने तैयारी चल रही है। इधर, वसुंधरा राजे के फिर से सियासत में ऐक्टिव होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी से अपनी दूरी बना ली।

सिमी आतंकी को कड़ी सुरक्षा में लाए जेपी अस्पताल

भोपाल सेंट्रल जेल से सिटी स्कैन करवाने लाए थे, मुंह के कैंसर का मरीज है आमिल परवेज

भोपाल (नप्र)। सिमी आतंकी आमिल परवेज (50) को कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जेपी अस्पताल लाया गया। आमिल को मुंह का कैंसर है। इससे संबंधित सिटी स्कैन और कई अन्य जांच के लिए उसे भोपाल सेंट्रल जेल से लाया गया था। करीब एक घंटे तक उसकी कई तरह की जांच की गई। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे का कहना है कि आमिल का रूटीन चैकअप के तहत सिटी स्कैन होना था।

वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल कर्नाटक में किसानों से मिले

बोले-वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन और ऐतिहासिक स्मारक पर दावा कर रहा, जांच करेंगे

हुबली (एजेंसी)। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल गुरुवार को कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने हुबली और विजयपुरा में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। जगदंबिका पाल ने कहा, उत्तरी कर्नाटक के किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर दावा कर रहा है। मैंने पूछा है कि क्या उनके पास जमीन का मालिकाना हक है। उनका कहना है है कि वे 50-70 साल से अधिक समय से वहां रह रहे हैं। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि, वक्फ बोर्ड उन स्थानों पर भी दावा कर रहा है, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक हैं। हम दोनों मामलों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। कमेटी मेंबर्स बोले- यह एकतरफा फैसला, अकेले जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ जगदंबिका पाल के अकेले कर्नाटक दौरा करने पर जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पाल का अकेला जाना सही नहीं है। यह एकतरफा फैसला है। यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसे समिति ने मंजूरी नहीं दी है। ये चेयरमैन का पर्सनल फैसला है। दरअसल, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने 5 नवंबर को एक्स पर लिखा- जेपीसी के चेयरमैन मेरी अपील पर हुबली और विजयपुरा जाएंगे, जहां वो वक्फ से प्रभावित किसानों और उनके संगठनों से मिलेंगे। किसानों की शिकायतें जेपीसी के सामने रखी जाएंगी। कर्नाटक के विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोग्गा के कुछ किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर नोटिस भेजे गए थे। इसके खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसे भाजपा ने भी सपोर्ट किया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान और जिला अधिकारियों के बीच एक बैठक के बाद, बिना किसी पूर्व सूचना के विजयपुरा में 44 संपत्तियों के लैंड रिकॉर्ड में वक्फ का नाम जोड़ा गया। विवाद बढ़ने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था उन्होंने अधिकारियों से नोटिस वापस लेने को कहा है, लेकिन भाजपा ने प्रदर्शन तेज किया।

कुछ भी कर लो, जम्मू-कश्मीर में 370 इतिहास ही रहेगा

- फिर विधानसभा में क्यों हो रही लड़ाई, बीजेपी का हंगामा जारी
- दो संविधान और दो निशान के खात्मे पर लगी है 'सुप्रीम' मुहर

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन अनुच्छेद-370 को लेकर हंगामा हुआ। बुधवार को बीजेपी के विरोध के बीच जम्मू-कश्मीर के विधानसभा में 370 दोबारा लागू करने का प्रस्ताव पास हो गया। यह प्रस्ताव केंद्रशासित प्रदेश के डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह बड़ी चालाकी से इस बिल के प्रस्तावक चुनने में संकेतों का इस्तेमाल किया। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी हिंदू हैं और जम्मू के नौशेरा से चुने गए हैं। दूसरे दिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अब हंगामे के कारण अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या 370 को दोबारा लागू किया जा सकता है। अगर नहीं तो केंद्रशासित प्रदेश की नई सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव क्यों पारित किया। बीजेपी का दावा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसे दोबारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह दावा सही है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों बेंच की मुहर लग चुकी है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने को वैध बताया था।

वायुसेना के पहले तेजस मार्क 1ए में हो रही देरी

- इंजन अमेरिकी कंपनी बना रही; विमान एचएएल के जिम्मे

बेंगलुरु (एजेंसी)। भारतीय वायु सेना को पहले एलसीए मार्क-1ए फाइटर जेट (तेजस) विमान के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस विमान को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (हॉल) बना रहा है। इंजन की सप्लाई अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक करेगी। जनरल इलेक्ट्रिस ने पहले फरवरी-मार्च में डिलीवरी का वादा किया था। फिर अक्टूबर तक सप्लाई की बात की। मगर इसमें अभी और देरी है। वहीं हॉल विमान और एयरफ्रेम पर काम कर रहा है। इंजन आते ही एयरक्रॉफ्ट की पहली खेप तैयार कर ली जाएगी।

भोपाल के वन विहार में घूमना महंगा

टू-व्हीलर पर घूमने के 60 की जगह 80 रुपए लगेंगे, विदेशियों को डबल चार्ज देना पड़ेगा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में घूमना महंगा हो गया है। टू-व्हीलर पर 2 सवारी घूमने पर अब 60 की जगह 80 रुपए देने होंगे। पैदल, कार-जीप या जिप्सी, मिनी बस और बड़ी बस से घूमने पर 5 रुपए से 200 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। विदेशियों को दोगुना चार्ज देना होगा। हालांकि, अभी ये रेट लागू नहीं किए गए हैं। यह नेशनल पार्क राजधानी के बीचोंबीच स्थित है, जहां टाइगर, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, हिरण, बारहसिंघा सहित 1600 से अधिक जानवर हैं। हर रोज हजारों टूरिस्ट नेशनल पार्क में पहुंचकर इन जानवरों का दीदार करते हैं। पहले यहां सफेद बाघिन भी थी, जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, बावजूद इसके पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इसी बीच अब घूमने के लिए नए रेट जारी किए गए हैं।

हर तीन साल में होती है 10 प्रतिशत वृद्धि

बता दें कि नेशनल पार्कों में हर तीन साल में 10 प्रतिशत तक शुल्क वृद्धि होती है। इस बार भी सरकार ने 1 नवंबर से नया शुल्क लागू कर दिया है। ऐसा ही बदलाव रालामंडल अभयारण्य, इंदौर और मुकुंदपुर चिड़ियाघर, मैहर में भी किया गया है।

अब 25 से 2200 रुपए तक किराया

वन विहार समेत अन्य तीन नेशनल पार्कों में अब न्यूनतम शुल्क 25 और अधिकतम 2200 रुपए तक हो गया है। बड़ी बस में सफर कर घूमने का मजा लेने पर 2200 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 2000 रुपए था। वहीं, पैदल भ्रमण पर 20 की जगह अब 25 रुपए देने होंगे।

छठ पूजा का पर्व सबके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान सूर्य की उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व 'छठ पूजा' की समस्त प्रदेश व देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि छठ पूजा का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। छठी मैया की कृपा सभी पर अनवरत बरसती रहे, सबके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का वास हो, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में कहा कि बहनें छठ पर्व पर अपने सुहाग की दीर्घ आयु, परिवार में सुख-समृद्धि और आनंद की कामना के साथ भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण कर अल्पाहार ग्रहण करती हैं। बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति की दीर्घायु के लिए कठिन साधना करती हैं, यह सनातन संस्कृति का वैशिष्ट्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जिन तालाब, नदी, पोखर आदि के किनारे छठ मैया की पूजा होती है, वहां उपयुक्त साफ-सफाई और सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने पर 48 आउटसोर्स बिजली कर्मचारी किए गये ब्लैक लिस्टेड

- मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने भोपाल, ग्वालियर, गुना एवं शिवपुरी में की कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने पर कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, ग्वालियर, गुना एवं शिवपुरी में बाह्य स्त्रोत (आउटसोर्स) एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 48 आउटसोर्स कार्मिकों को सेवाओं से पृथक करते हुए ब्लैक लिस्ट किया है। कंपनी द्वारा ब्लैक लिस्ट किये गए 48 आउटसोर्स कार्मिक कंपनी कार्य क्षेत्र के किसी भी बिजली कार्यालय में कार्य नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल वृत्त में कार्यरत 18 आउटसोर्स कार्मिकों के साथ ही हरदा में 03, शिवपुरी वृत्त के 07 एवं ग्वालियर वृत्त में 06, दतिया वृत्त में 02, तथा गुना वृत्त में कार्यरत 12 आउटसोर्स कार्मिकों को लापरवाही और अनियमितता बरतने के कारण सेवा से पृथक कर ब्लैक लिस्ट किया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने सचेत किया है कि कार्य में पारदर्शिता, लगन, निष्ठा और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ता सेवाओं और कंपनी की उत्तरोत्तर तरक्की के लिए निरन्तर प्रयास करते रहें।

छिंदवाड़ा में 5 ग्राम ड्रग्स के साथ 4 पकड़ाए

- आरोपियों के पास से 5 मोबाइल और सवा 2 लाख रुपए का माल बरामद

छिंदवाडा (नप्र)। छिंदवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत चार आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से 5 ग्राम एमडी ड्रग्स पाउडर बरामद हुआ है। एसपी के अनुसार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन में शामिल अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस कड़ी में 6 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अजीत चौधरी ग्राम गंगेरुआ जिला सिवनी, चित्रांश चौहान बिरहोली, जिला सिवनी, प्रियांशु डेहरिया मधुबन कॉलोनी छिंदवाड़ा और साहिल शाह सागरपेशा छिंदवाड़ा शामिल हैं।

लाड़ली बहना अच्छी योजना थी तो शिवराज को क्यों हटाया

सचिन पायलट बोले- भाजपा लोगों को राशन दे तो दानदाता, कांग्रेस गरीब की मदद करे तो रेवड़ी

भोपाल (नप्र)। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुरुवार को भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के साथ मीडिया से चर्चा की। पायलट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, शिवराज सिंह चौहान द्वारा मप्र में शुरू की गई लाड़ली बहना योजना इतनी अच्छी थी तो उनको यहां से हटाया क्यों गया? इतने सालों से वह काम कर रहे थे, तो उनको मजबूरन यहां से क्यों जाना पड़ा? ये लोग फ्रीबीज की जो बात कर रहे हैं ये बड़ा अजीब है कि जो फ्रीबीज को परिभाषित करने वाले लोग हैं वह श्रेय लेते हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन खिला रहे हैं, वह तो ठीक है। अगर गरीब, वंचित लोगों को कांग्रेस की सरकार अगर अनुदान देना चाहे, मदद करना चाहते तो वह रेवड़ी है वह फ्रीबीज़ है।

बीजेपी 80 करोड़ लोगों को राशन दे तो अन्नदाता, कांग्रेस करे तो रेवड़ी

पायलट ने कहा- खुद आप श्रेय ले रहे हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन करा रहे हैं, यानि आप करें तो वह अन्नदाता और दानदाता हैं। कांग्रेस कुछ घोषणा करे तो आप उसको रेवड़ी मानते हैं। कांग्रेस की सरकार चाहे वह तेलंगाना की है चाहे

कर्नाटक की है या कहीं की भी है। जो हमने कहा वह करके दिखाया। कल भी हमने जो महाराष्ट्र में 5 गारंटी लॉन्च की हैं हमारी पार्टी का इतिहास और ये अनुभव है कि हम जो कहते हैं वह कर रहे हैं।विजयपुर उपचुनाव में पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आए पायलट पीसीसी चीफ पटवारी के भोपाल स्थित निवास पर पहुंचे।

दूसरों पर दोषारोपण करना बीजेपी की प्रवृत्ति

हमने नहीं कहा था कि हम दो करोड़ रोजगार देंगे। भाजपा ने कहा था वो नहीं कर पाए। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कहा था वो भी नहीं कर पाए। किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, नहीं कर पाए। तो झूठ बोलना और फिर विपक्ष को कोसना ये कब तक करेंगे? आपके पास सत्ता है यहां आपका डबल इंजन चल रहा है। मध्य प्रदेश में इतने सालों से आपकी सरकार है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्यों महंगाई बढ़ रही है? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? उस पर अंकुश कौन लगाएगा औरों पर दोषारोपण करना भाजपा की प्रवृत्ति में आ चुका है। पिछली संसद में 147 सांसदों को एक दिन में निष्कासित किया गया, ये आज तक नहीं हुआ। अब हमारा संख्या बल बहुत बेहतर है, तो हम वहां सार्थक चर्चा भी करवाएंगे और मनमाने तरीके से सरकार जो एकतरफा फैसला लेती थी उस पर अंकुश लगेगा।

मप्र में भाजपा ने वादों को पूरा करने की कोशिश नहीं की: पायलेट ने कहा- मैं, तन्खा जी और जीतू भाई आज मप्र उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार करने के लिए मप्र आयें हैं। असल बात ये है कि मध्य प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है। सरकार गठन के बाद जिन उम्मीदों को लेकर जनता ने वोट डाले थे, जिन मोदी गारंटियों और जिस मेनिफेस्टो को लेकर वे (भाजपा) जनता के बीच में गए थे। इन 11- 12 महीनों में किसी सूरत में इस नई सरकार ने उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं की। अगर सरकार सच्चे मन से कोशिश करती और नाकाम रहती तो हम समझ सकते थे।

बीसीसीआई की मांग - कमर्शियल टैक्स खत्म हो

अध्यक्ष पाली बोले-एमपी में कहीं नहीं तो भोपाल में क्यों? मेयर बोलीं-विचार करेंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में व्यापारियों की शीर्ष संस्था भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने ट्रेड (कॉमर्शियल) और प्रोफेशनल टैक्स को खत्म करने की मांग फिर उठाई है। अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली ने शहर भर के व्यापारियों की मौजूदगी में कहा कि एमपी में यह टैक्स कहीं नहीं लिया जा रहा, तो फिर भोपाल में ऐसा क्यों है? जवाब में मेयर मालती राय ने कहा कि इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष पाली ने सांसद आलोक शर्मा से प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन पर भी मांग रखी। कहा कि कुछ महीने पहले ही गाइडलाइन बढ़ाकर प्रॉपर्टी के रेट महंगे किए जा चुके हैं। अब फिर से नई गाइडलाइन ला रहे हैं। जिस पर सांसद शर्मा ने कहा कि इस मसले पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की है। आम लोग और जनप्रतिनिधियों के सुझाव के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मौजूदा गाइडलाइन रोक दी गई है।

इन दो टैक्स का विरोध कर रहे व्यापारी : एक्सपर्ट अनिल कुमार चुग ने बताया, नगर निगम सीमा में पहले जो भी व्यापार होता था, उसके बदले कुल 254 कैटेगरी का टैक्स लिया जाता था। जगह के हिसाब से अलग-अलग टैक्स होता था, जो सलाना वसूला जाता था। इसका सरलीकरण करने के लिए 4, 5 और 6 रुपए प्रति स्क्वायर प्रतिवर्ष के हिसाब से टैक्स लेना शुरू किया गया। यानी, यदि टैक्स 6 रुपए स्क्वायर फीट है और ऑफिस-दुकान 1 हजार स्क्वायर फीट है तो 6 हजार रुपए टैक्स चुकाना होता है, जबकि पहले यह सिर्फ साढ़े 4 सौ रुपए ही लगता था। मुख्य रोड और गली में

अलग-अलग कर लिया जाने लगा। इसका विरोध कर रहे हैं।

दूसरा टैक्स किराए पर चढ़ी बिल्डिंग से वसूला जाना है। इसे प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जोड़ दिया गया है। जिससे बिल्डिंग मालिक पर पूरा लोड आ गया, जबकि जो किराए पर रह रहा है, उससे ही वसूला जाना चाहिए। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से यह मांग की गई थी। जिसके बाद यह टैक्स हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से जोड़कर आने लगा है। जिससे व्यापारियों की कमर टूट गई है।

सांसद का नागरिक अभिनंदन हुआ: लिंक रोड नंबर-1 स्थित गुजराती भवन में बुधवार रात में बीसीसीआई का दिवाली मिलन समारोह हुआ। सांसद आलोक शर्मा मुख्य अतिथि थे। विधायक भगवानदास सबनानी, आरिफ मसूद, आतिफ अकील, महापौर राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, बीजेपी नेत्री नेहा बग्गा, मनमोहन अग्रवाल, कांग्रेस नेता गोविंद गोयल, कैलाश मिश्रा, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष संतोष अग्रवाल समेत कई अतिथि मौजूद थे। सभी का स्वागत अध्यक्ष पाली ने किया, जबकि स्वागत भाषण महासचिव आदित्य जैन मनयां ने किया। कार्यक्रम में सांसद शर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन उपाध्यक्ष सुनील जैन ने किया।

इन संगठनों के प्रमुख रहे जिम्मेदार: क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक, बैरागढ़ कपड़ा मार्केट अध्यक्ष कन्हैयालाल इसरानी, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र धाकड़, करोंद मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी, मंडीदीप के उद्योगपति संजीव जैन, बेस्ट टीम के फाउंडर स्पर्श द्विवेदी, भोपाल सिटी ग्रुप के आनंद शर्मा समेत बड़ी संख्या में विभिन्न ट्रेडों का व्यापार कर रहे व्यापारी, कारोबारी मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत उपाध्यक्ष जैन, आकाश गोयल, आदित्य जैन, कृष्णकुमार बांगड़, संजीव जैन, रोहित जैन, दीपक पसारी, बलदेव खेमानी, संजीव कुमार जैन आदि ने किया। संचालन प्रवक्ता अजय देवनानी ने किया।

बिजली उपभोक्ता अब उपाय ऐप के जरिए भी करा सकेंगे केवायसी

भोपाल (नप्र)। राज्य शासन की लाभकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को ईकेवायसी कराना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप के जरिए भी ईकेवायसी करा सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध उपाय ऐप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया के तहत अब तक 04 लाख 11 हजार 022 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। कंपनी ने बताया है कि केवायसी प्रक्रिया के तहत नर्मदापुरम ग्रामीण में 48 हजार 024, बैतूल ग्रामीण में 71 हजार 171, राजगढ़ ग्रामीण में 24 हजार 473, शहर वृत्त भोपाल में 30 हजार 732, भोपाल ग्रामीण में 32 हजार 187, गुना ग्रामीण में 28 हजार 257, विदिशा ग्रामीण में 34 हजार 198, सीहोर ग्रामीण में 17 हजार 598, ग्वालियर ग्रामीण में 13 हजार 627, शहर वृत्त ग्वालियर में 14 हजार 140, अशोकनगर ग्रामीण में 12 हजार 621, दतिया ग्रामीण में 14 हजार 685, रायसेन ग्रामीण में 18 हजार 141, शिवपुरी ग्रामीण में 15 हजार 491, हरदा ग्रामीण में 12 हजार 912, श्योपुर ग्रामीण में 05 हजार 921, मुरैना ग्रामीण में 10 हजार 889 एवं भिण्ड ग्रामीण में 05 हजार 955 बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी की गई है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है।

नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही केवायसी से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन एवं उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी तथा कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पचमढ़ी-अमरकंटक समेत 6 शहरों में पारा 15 डिग्री से नीचे

हवा के रुख से एमपी में तेज होगी ठंड; 15 नवंबर से धुंध भी बढ़ेगी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में फिलहाल उत्तर-पूर्वी हवाएं चल रही हैं। जब इनका रुख उत्तर-पश्चिमी हो जाएगा और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, तब यहां के तापमान में और गिरावट होगी। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से ग्वालियर-चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। 15 नवंबर से सुबह-शाम धुंध भी बढ़ेगी। हवाओं का असर इन्हीं संभागों में

सबसे पहले होता है। फिलहाल, प्रदेश में 6 शहरों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी और अमरकंटक सबसे ठंडे हैं। पचमढ़ी में टेम्प्रेचर 11.2 डिग्री सेल्सियस है। मौसम वैज्ञानिक शिल्पा आप्टे ने बताया-15 नवंबर से ठंड का असर तेज हो सकता है। पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। एक सप्ताह तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। दिन में पारा 30 डिग्री से ज्यादा रहेगा जबकि रात में पारा 12 से 20 डिग्री के बीच बना रहेगा।

अभी ये शहर सबसे ठंडे

मौसम विभाग के अनुसार, अभी नर्मदापुरम-अनूपपुर जिले सबसे ठंडे हैं। मंगलवार-बुधवार की रात में पचमढ़ी में पारा 11.2 डिग्री और अमरकंटक में 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मंडला, शाजापुर, सीहोर और शहडोल ऐसे जिले हैं, जहां पारा 15 डिग्री से नीचे है। भोपाल, नौगांव, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, राजगढ़, मलाजखंड, उमरिया, जबलपुर, टीकमगढ़, सिवनी, खंडवा, उज्जैन, खरगोन, रीवा, धार, खजुराहो और ग्वालियर में पारा 18 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। सर्दी का असर बढ़ते ही मध्यप्रदेश के शहरों में सुबह-शाम धुंध होने लगी है।

दिन में भी पचमढ़ी सबसे ठंडा

पचमढ़ी रात के साथ दिन में भी सबसे ठंडा है। बुधवार को यहां दिन का तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बैतूल, नौगांव और मलाजखंड में तापमान 30 डिग्री के नीचे जबकि बाकी शहरों में इससे अधिक रहा।

आदिवासियों पर फोकस

वनाधिकार कानून और पेसा नियमों को लेकर टास्क फोर्स बनाई, 3 माह में देगी पहली रिपोर्ट

- सीएम होंगे अध्यक्ष, जनजातीय, पंचायत और वन मंत्री होंगे उपाध्यक्ष

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में वनभूमि पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने संबंधी वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) और पेसा नियमों के प्रभावी और टाइम बाउंड क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने टास्कफोर्स गठित कर दी है। यह टास्क फोर्स मप्र की वन भूमि पर समुदाय के सामूहिक वन संसाधनों पर अधिकारों के लंबित मुद्दों और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी सिफारिशें करेगा। इस टास्क फोर्स में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति और 13 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई है।

दोनों ही समितियों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बनाया गया है। शीर्ष समिति में जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वन मंत्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव अनुराग जैन को पदेन सदस्य सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग को पदेन सह सदस्य सचिव बनाया है।

कार्यकारी समिति में सीएस, एसीएस पंचायत व ग्रामीण विकास, वन, जनजातीय कार्य विभाग व टीआरआई के अपर आयुक्त को पदेन सदस्य बनाया है।

कानून विशेषज्ञ के रूप में डॉ. मिलिंद दांडेकर और विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉ. शरद लेले, मिलिंद थत्ते की नियुक्ति की गई है। जनजातीय वर्ग से दो पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम व राम डांगोरे को भी सदस्य बनाया है। जनजातीय मंत्रणा परिषद से डॉ. रूपनारायण मांडवे और कालू सिंह मुजाल्दा को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

इस बारे में बताया गया है कि वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से सीएम की अध्यक्षता में शीर्ष समिति की बैठक होगी। वहीं कार्यकारी समिति की बैठक सीएम के निर्देश पर कभी भी बुलाई जा सकेगी। यह समिति 3 माह के भीतर प्रदेश में वनाधिकार कानून और पेसा नियमों के मौजूदा क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट देगी।

ये काम करेगा टास्क फोर्स

- वनाधिकार अधिनियम में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों की जिलावार मेपिंग कर सूची तैयार कराएगा। प्रदेश में अन्य संभावित क्षेत्रों के को चिन्हित करने की सिफारिश भी करेगा।
- सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन कराएगा।
- पेसा और एफआरए के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को सिफारिश करेगा।
- एफआरए के जुड़े मामलों पर जिला स्तरीय कमेटी (डीएलसी) और पेसा संबंधी विषयों के लिए जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्ययोजना की सिफारिश करेगा।
- अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य-योजना एवं समय-सीमा के अनुसार बिंदुवार क्रियान्वित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना करेगा।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दो अहम फैसले सुनाए हैं, जिनका आमतौर पर स्वागत किया गया है। हालांकि इन फैसलों के दूरगामी परिणामों को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं, जिनका समाधान भी जरूरी है। देश की सर्वोच्च अदालत का एक बड़ा फैसला देश में निजी सम्पत्ति के सरकार द्वारा अधिग्रहण का है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर निजी सम्पत्ति सरकार नहीं ले सकती है। इस महत्वपूर्ण मामले में शीर्ष अदालत की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिए गए अपने ही फ़ैसले को पलट दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने 7-2 के बहुमत से यह फ़ैसला दिया। अपने फ़ैसले में बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। कुछ ख़ास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर सकती है। यह निर्णय ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फ़ैसले को खारिज़ कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकारें अधिग्रहित कर सकती हैं। इसी संदर्भ में सीजेआई की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि पुराना फ़ैसला ख़ास आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। लेकिन कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं, जिन्हें समुदाय, सार्वजनिक भलाई के लिए रखा गया है। गौरतलब बात यह है कि 9 जजों की बेंच अमूमन संवैधानिक महत्व से जुड़े मामलों के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन लगता कोर्ट ने सम्पत्ति के अधिकार के प्रश्न को भी बहुत गंभीरता से लिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) में कहा गया है कि सरकार की नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के संसाधनों को इस तरह से बाँटा जाए कि वे सभी के भलाई के काम आएं। इसी आधार पर सरकार को कानून बनाने चाहिए। जानकारों के अनुसार इस फैसले का असर केवल संपत्ति क़ानूनों पर नहीं बल्कि दूसरे क़ानूनों पर भी पड़ेगा। मौजूदा समय में संपत्ति का अधिकार महज़ अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। वैसे भी संपत्ति अधिग्रहण करने का मामला हमेशा विवादों से भरा रहा है। जब 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण क़ानून लाना चाहा, तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की एनडीए सरकार इस क़ानून में बदलाव लाना चाहती थी लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रही। दूसरा फैसला उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को संवैधानिक ठहराने का है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब सरकार को सार्वजनिक कामों के लिए निजी जमीन अधिग्रहण में दिक्कत आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि यह धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। यूपी में यह मदरसा एक्ट तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के समय लागू हुआ था। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट द्वारा इसे खारिज करने के बाद राज्य के 16 हजार मदरसों के बच्चों के सामने संकट खड़ा हो गया था। उन्हें इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसे केवल 12 तक की शिक्षा दे सकते हैं, उससे ऊपर कामिल और फाजिल की शिक्षा देने का उन्हे अधिकार नहीं है। जो बच्चे आगे की शिक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें सामान्य कॉलेजों में ही प्रवेश लेना होगा। ऐसे बच्चों को दिक्कत आ सकती है। इसका समाधान भी करना होगा।

ट्रंप की वापसी से भारत को मिलेगा लाभ

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। संप्रति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के डॉ. आंबेडकर चेयर में चेयर प्रोफेसर हैं।

अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर मोमेंट डोनॉल्ड ट्रंप के आने से यूं लग रहा है क्योंकि ट्रम्प और मोदी की अच्छी दोस्ती रही है। दोनों में सहजता है। दोनों में मैत्री है। इस कारण से भी यह कहा जा सकता है कि देश आपस में मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि 2019 में टेक्सास में 'हाउडी, मोदी!' रैली में दोनों नेता एक साथ दिखे थे। टेक्सास में ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की मेजबानी की थी। यह किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। इस सभा में जब मोदी-मोदी के नारे लगे थे तो ट्रम्प भी घबरा गए थे कि यह क्या हो रहा है? मोदी आखिर कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। उन्होंने यह मान लिया था कि मोदी एक करिश्माई प्रधानमंत्री है और इससे हमें बनाकर रखना चाहिए।

अमेरिका में राष्ट्रपति वायडेन की बिदाई हो गई। ट्रंप पुनः एक बार 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में स्थापित हो चुके हैं। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, उन्हें करारी हार मिली है। कमला हैरिस अमेरिका में भारत की विदेश नीति को ज्यादा महत्व दे सकती थीं लेकिन उन्होंने वायडेन के साथ उप राष्ट्रपति रहते हुए भारत का उतना साथ नहीं दिया जिस प्रकार वह दे सकती थीं और भारत की भूमिका को ज्यादा मजबूत बना सकती थीं। हैरिस से ज्यादा आत्मीय ऋषि सुनके भारत की संस्कृति से जुड़े रहे। वह भारत के साथ रिश्ते को निभाए और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने जो हिन्दू व हिंदुस्तान के पक्ष में कहा वह पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने लंदन में यूके के अन्य भूभाग में मंदिरों और हिंदुओं के बीच जाकर सम्मान दिया उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। यह उम्मीद भारतवासियों को कमला हैरिस से भी थी क्योंकि उनके भी परिवार के लोग भारत में हैं और वह भारत की ही हैं, ऐसा पूरा देश मानता है। वह वॉयडेन के साथ मिलकर अनेक साझे संकल्प व विजन के साथ आगे बढ़ सकती थीं। इसके बजाय भारत के प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उतने दीं। वायडेन ने जो अमेरिकी नागरिकों की इमिग्रेन्स के बरक्स मौजूदा कानून था उसे अमेरिकियों के पक्ष में मजबूत होने दिया।

कमला हैरिस के हारने के जो भी कारण रहे हों, वह एक बहस का अब हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि वायडेन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाराज़गी है। इज़रायल के साथ अमेरिकी संबंध हों, रूस व यूक्रेन समस्या हो, किसी भी मोर्चे पर वॉयडेन और हैरिस की जोड़ी संतुष्ट नहीं कर पायी। क्लाइमेट चेंज के सम्मेलन हों या समिट फ़ॉर फ्यूचर वायडेन ने कोई प्रभावकारी पक्ष नहीं।रख पाए। उनसे अमेरिका की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के ईसूज भी हल नहीं हुए तो यह व्यापक असंतोष का कारण बना। इन सबके साथ कमला हैरिस से जो नई अमेरिकी सोच की आबादी जुड़ी वह भी निराश हुई। ऐसे में ट्रम्प का एक बार बढ़त बनाकर जनता का विश्वास जीतना लाज़मी था। पलट गई अमेरिका की राजनीति। ट्रम्प को जो जीत हासिल हुई उसके पीछे उनके साथ घटी हिंसक घटना भी रही है जिसने उत्प्रेरक का कार्य किया और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ट्रम्प की मदद की। अमेरिका में इस साल पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के दो बार प्रयास किए गए, प्रचार के बीच एक राष्ट्रपति उम्मीदवार ने अपने कदम वापस खींच लिया, 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के खर्च और बेहद विवादित प्रचार अभियान के बाद आखिरकार डॉनल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव 2024 जीतकर राष्ट्रपति बन ही गए. यह जीत ऐतिहासिक है और उनके लीडरशिप व ताकत का सही प्रदर्शन बन गई है।

फिलहाल व्हाइट हाउस में जो ट्रम्प के रूप में नई सुबह होने जा रही है, उसके विशेषज्ञ और प्रेक्षक अपने-अपने मायने निकाल रहे हैं। ट्रंप रिश्क लेने वाले लोगों में सुमार किए जाते हैं। ज़िद्दी हैं। अमेरिकी बिज़नेस कम्युनिटी उन्हें मानती है। वह खुद उम्दा कारोबारी हैं और लोगों को सपने बेचना जानते हैं, रिझाना जानते हैं। तभी तो ऐसे में वो लोगों के बीच अपनी करिश्माई छवि एक बार फिर से बनाने में सफल रहे।

अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर मोमेंट डोनॉल्ड ट्रंप के आने से यूं लग रहा है क्योंकि ट्रम्प और मोदी की अच्छी दोस्ती रही है। दोनों में सहजता है। दोनों में मैत्री है। इस कारण से भी यह कहा जा सकता है कि देश आपस में मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि 2019 में टेक्सास में 'हाउडी, मोदी!' रैली में दोनों नेता एक साथ दिखे थे। टेक्सास में ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की मेजबानी की थी। यह किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है। इस सभा में जब मोदी-मोदी के नारे लगे थे तो ट्रम्प भी घबरा गए थे कि यह क्या हो रहा है? मोदी आखिर कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। उन्होंने यह मान लिया था कि मोदी एक करिश्माई प्रधानमंत्री है और इससे हमें बनाकर रखना चाहिए। यद्यपि ज्यादा लाभ उस समय ट्रम्प को नहीं मिला वायडेन जीत गए। लेकिन वॉयडेन का एक कार्यकाल उनके लिए और ट्रम्प के लिए सबक लेने वाला माना जाएगा। एक हार गया, एक जो हार गया था, वह फिर भारी अंतरों से जीत गया। यह एक मौका था जब भारतीयों ने यह बताया कि उनकी वास्तविक सोच क्या है। भारतीय अपनी समझ से ही किसी को सहयोग करते हैं। ट्रम्प इस बार जीतकर भारतीयों के सहयोग को नहीं भूल पाएंगे और यह उम्मीद है कि कोई गलती न करके भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर आगे बढ़ेंगे। कूटनीतिक रूप से जब भारत को आज़ अमेरिका की जरूरत भारत को भी है तो भारत तो अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रहेगा ही। ज़रूरत यह है भारत की यदि संयुक्त राष्ट्र का विस्तार होता है तो अमेरिका उसका साथ दे। हमारे बहुपक्षीय विकास व विस्तार के लिए आर्थिक साझेदारी बढ़े। हमारी सांस्कृतिक व शैक्षणिक निवेश व साझेदारी बढ़े। भारत और अमेरिका के बीच इमिग्रेशन के मसले भी सरल बनाए जाएं और साथ ही ट्रम्प अमेरिका में भारतीय लोगों का बहुआयामी प्रतिभागिता व प्रतिस्पर्धा के लिए कानून को सरल बनाएँ।

अभी दुनिया के सामने ट्रम्प ने भी चुनौती खड़ी की है उससे भी उन्हें जूझना है जैसे अमेरिकी हिंसक गतिविधि को उन्हें कम करना है। अमेरिका में आर्थिक सुधार करना है। अमेरिकी जनता का अंतःकरण जीतना है जो उन्होंने पहले खोकर अब ज्यादा संजो पाने में थोड़ा सफल हुए हैं और साथ ही अब ट्रम्प को जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर काम करना है और युद्धों व परमाणु खतरों से उन्हें अमेरिका को अलग करना है। ट्रम्प के सामने यह चुनौतियां कोई आसान नहीं हैं। ट्रम्प ने ऐतिहासिक रूप से जो जीत हासिल की है तो ऐसा उन्हें करना होगा कि वे ऐतिहासिक व साहसिक कार्य के लिए जाने जाएँ।

भारत बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और अपनी लीडरशिप से भारत की प्रतिष्ठा को अर्जित कर रहा है। अब ट्रंप को पुनः सत्ता में आने से भारत को लाभ मिलने जा रहा है। हमारे देश का कूटनीतिक संबंध अमेरिका के साथ बढ़ेगा। भारत का आम नागरिक अपने निजी हितों को ज्यादा समझता है लेकिन जब राष्ट्रों के बीच मैत्री व सद्भाव के मसले आते हैं तो वहां हमारे कूटनीतिक संबंध बहुत अहम हो जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी हमारे रणनीतिकारों की होती है और आम जन भी यही चाहता है कि हमारे देश की हमेशा प्रतिष्ठा बढ़े। हमारे अभी तक जो अमेरिकी संबंध हैं, वह थोड़ा जो तल्खी के साथ बढ़ रहे थे। ट्रम्प के आने से निःसंदेह वह सहज और सद्भावपूर्ण होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ रिपब्लिकन पार्टी को मिली सफलता के लिए ट्रम्प को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी शानदार और जबरदस्त जीत उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता के प्रति अमेरिकी जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है। साथ ही प्रधानमंत्री यह कहना नहीं भूले की प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम एक साथ हों। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री स्वयं खुश हैं और वह भारत को अमेरिका के साथ जोड़कर कुछ विशेष रणनीति के साथ भारत को आगे बढ़ने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

एमएसपी से किसानों को भरोसा देने की कोशिश

कृषि योजना

अमित बैजनाथ गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। यह वृद्धि न्यूनतम 130 रुपए एवं अधिकतम तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 2425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वृद्धि रेपसीड और सरसों के दाम में हुई है। इसमें प्रति क्विंटल तीन सौ रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह मसूर के दाम में 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकारी दर पर रबी फसलों की खरीद-बिक्री का सत्र अप्रैल, 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना हो चुकी है, जिसकी मांग किसानों की ओर से लगातार हो रही थी। सरकार की ओर से एमएसपी में अब तक 23 फसलों को शामिल किया जा चुका है। असल में एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा!

सबसे पहले एमएसपी को समझने की कोशिश करते हैं। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका मकसद किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरुआत साल 1967 में हुई थी। एमएसपी तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सीएसीपी उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग-आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। एमएसपी की गणना के लिए सीएसीपी खेती की लागत को तीन हिस्सों में बांटता है। इसमें फसल उत्पादन के लिए किसानों के नकदी खर्च के साथ-साथ पारिवारिक श्रम का भी हिसाब लगाया जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वे हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसलों की एक सूची सरकार को सौंपी थी। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन ये सरकार के रुख पर निर्भर करता है। किसान चाहते हैं कि सरकार तमाम फसलों के लिए जो एमएसपी घोषित करती है, उसकी गारंटी दी जाए। अगर सरकार ये गारंटी देती है, तो फसलों का विविधीकरण अपने-आप हो जाएगा। अगर दलहन और तिलहन बेचने से किसान को ज्यादा मुनाफा होगा, तो वो धान और गेहूं क्यों पैदा करेगा। सरकार और इस देश के बुद्धिजीवी चाहते हैं कि फसलों का विविधीकरण हो। ये अच्छी बात है, लेकिन किसानों को ये गारंटी तो मिले कि उसकी फसलें एमएसपी पर बिकेंगी।

एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के कई उपाय हो सकते हैं। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन यानी कि जब फसलों की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाए, तो सरकार इसकी भरपाई करे। वहीं किसानों को धान-गेहूं की फसल की बजाय ज्यादा कीमत देने वाली फसलों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को फल, सब्जी, मवेशी और मछली पालन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती हैं और किसानों को घाटा उठाना पड़ता है। इससे किसान कर्ज में डूब जाता है और कई मामलों में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है।

वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी व्यवस्था का दबदबा इस सेक्टर में इनोवेशन को हतोत्साहित करेगा। इससे किसान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर होकर रह जाएंगे और जोखिम लेने से डरेंगे, इसलिए किसानों को चावल-गेहूं की एमएसपी खरीद के चक्र से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का अहित करेगी। उनका दावा है कि अगर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के दाम बढ़ेंगे, तो खाद्य वस्तुओं के दाम 25 से 30 फीसदी बढ़ जाएंगे और सरकार के लिए महंगाई नियंत्रण बेहद कठिन हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल की पूरी खरीद की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। किसान जितनी फसल पैदा करेंगे, उसकी एमएसपी पर पूरी खरीद सरकार और उसकी एजेंसियों को करनी होगी। ऐसा करने से ही किसानों का भला होगा और फसलों का विविधीकरण भी पूरा हो जाएगा। सरकार को अपने फैसले किसानों को ध्यान में रखकर ही लेने होंगे।

इधर, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता देश के स्थायित्व और सम्मान का विषय है। एमएसपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप तंत्र भी साबित हुआ है। आयात द्वारा खाद्य सुरक्षा कतर, बहरीन आदि जैसे कम आबादी और मजबूत औद्योगिक आर्थिक आधार वाले देशों के लिए एक व्यवहार्य मॉडल हो सकता है। उनका दावा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दुनिया के बाकी देशों के लिए गेहूं का उत्पादन और निर्यात कर सकते हैं, लेकिन तब कृषि गतिविधियों से जुड़े भारतीयों सहित दुनिया की आधी आबादी बेरोजगार हो जाएगी। उनका कहना है कि कुछ मामलों में आयात की पक्षपातपूर्ण सरकारी नीति ने देश में तिलहन किसानों और खाद्य तेलों के उद्योगों को हानि पहुंचाई है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में ऐसी नीतियों से बचना चाहिए।

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस-ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (आईसीआरआईईआर-ओईसीडी) का एक अध्ययन बताता है कि खेती की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने की पक्षपाती सरकारी नीतियों के कारण देश के किसान वर्ष 2000 के बाद से लगातार घाटा उठा रहे हैं, जिसने किसानों को लगातार गरीबी रेखा से नीचे रखा हुआ है। रिपोर्ट आगे कहती है कि पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियों और कृषि कीमतों के कारण देश के किसानों को वर्ष 2022 में 14 लाख करोड़ रुपए और 2000-2017 के दौरान 2017 की कीमतों पर 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन पक्षपाती सरकारी नीति आधारित शोषण के कारण ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वहीं सरकार कहती है कि 2022-23 में किसानों से 60 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक धान और 26 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई और करोड़ों रुपए हस्तांतरित किए गए।

असल में एमएसपी के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं और चावल को भारतीय खाद्य निगम पीडीएस के तहत सक्रिय रूप से खरीदता है। कई राज्य सरकारें संपूर्ण अनाज की खरीद करती हैं, ऐसे राज्यों में किसानों को अधिकतम लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान प्रायः प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। सीएसीपी ने अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट में एमएसपी पर एक कानून बनाने का सुझाव दिया था। ऐसा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक बताया गया था। उसका कहना था कि सरकार को कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों द्वारा प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सके। ऐसा करने के लिए धान और गेहूं के एमएसपी को फ्रीज कर दिया जाए। इसके अलावा उनकी खरीद को प्रति किसान के हिसाब से सीमित कर दिया जाना चाहिए। वहीं किसानों को बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और खरीद करने वाले सरकारी अधिकारियों पर निर्भरता से बचाना चाहिए, ताकि उनका शोषण रोका जा सके।

तेल की धार, जारी है मार

मुद्दा

भूपेन्द्र गुप्ता

लेखक स्वतंत्र विश्लेषक हैं।

अभी-अभी कमर्शियल गैस कनेक्शन की कीमतों में 62 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी गई है। सरकार इस बात की बार-बार दुहाई दे रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो स्थिर हैं।

2014 में जब सरकार ने तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि की थी और पेट्रोल 59 रुपये प्रति लीटर से उछलते उछलते 108 रुपये तक पहुंचा था, तब बार-बार सरकार यह बताती थी कि तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है। जैसे-जैसे दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती हैं वैसे-वैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना सरकार की मजबूरी है। यह नीति मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने तब बनाई थी जब कच्चा तेल 120 डालर प्रति बैरेल पर घूम रहा था और कीमतों के दबाव से बचने के लिए उन्होंने आइल पूल डिफिसिट फंड बनाया था वह बाजार के उतार-चढ़ाव को एब्जार्व करता था। इसीलिये कच्चा तेल 124 डालर होने के बावजूद पेट्रोल 58-59 रुपये लीटर मिल रहा था।

अभी-अभी मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कई तथ्यों के साथ सामने आए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि देश ने जैव ईंधन यानि एथेनाल के मिश्रण से लगभग एक लाख 6 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है। विचारणीय है कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने जब एथनाल नीति बनाई थी तो उसका आशय यही था कि आयात निर्भरता घटाकर आम उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया जाये। वर्ष 2014 तक मिश्रित ईंधन की कैलोरिक गुणवत्ता प्रायोगिक और शुरुआती दौर में थी, अतः एथेनाल का प्रयोग पेट्रोल की कुल खपत का 1.53 फीसदी तक ही था।यह खपत अब 2023-24 में कुल खपत के 15 फीसदी तक पहुंच गई है ।लेकिन इस बचत का लाभ न तो उपभोक्ता को ही मिल रहा है न ही आयात निर्भरता में कमी ही आई है।2014 में हमारी सकल घरेलू खपत के मुकाबले आयात निर्भरता लगभग 70 फीसदी थी जो अब बढ़कर बकौल मंत्री हरदीप सिंह के 88 फीसदी पर पहुंच चुकी है। इसे नौ दिन चले अढ़ाई कोस ही कहा जा सकता है। क्योंकि अगर नीतियां सात-आठ साल में भी परिणाम न दें तो उनकी समीक्षा लाजिम हो जाती है।

इनवेस्टमेंट इनफार्मेशन एंड क्रेडिट कंपनी (ईक्रा) की रिपोर्ट बताती है कि कच्चे तेल की कीमतें 12 फीसदी कम हुईं है। रूस ने हमें बाजार से सस्ता क्रूड आइल देकर विगत तीन साल से निहाल किया है। इसका लाभ न तो उपभोक्ता को मिला न ही अर्थव्यवस्था को। विभिन्न तकनीकि अनुमान बताते हैं कि अगर एक डालर प्रति बैरैल कच्चे तेल की कीमत घटती है तो कंपनियों को 13 हजार करोड़ की बचत होती है ।कच्चा तेल 84 डालर प्रति बैरेल से घटकर 72 डालर पर आ गया है यानि 12 डालर प्रति बैरेल कीमतें गिर गईं हैं। जबकि एक सरकारी आंकड़े के अनुसार मार्च से अब तक 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 12 रुपये प्रति लीटर डीजल पर मुनाफा बढ़ गया है। 60 हजार करोड़ की आयात बिल में बचत हुई है। 544 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आयी है। देशी सरकारी कंपनियों इंडियन आइल को 39 हजार 619 करोड़, भारत पेट्रोलियम को 26हजार 673 करोड़ एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को 14 हजार 694 करोड़ का मुनाफा हुआ है अगर इसी अनुपात में कीमतें भी घटतीं तो परिवहन कास्ट कम से कम 20 फीसदी नीचे आ जाती।

परिवहन घटता तो उत्पादन की कीमतें घटतीं, महंगाई नीचे आती आम नागरिक के जेब में पैसा बचता तो आर्थिक गतिविधियां तेज होतीं। खपत बढ़ती और इस मुनाफे की खुशी भारत के आम व्यक्ति के चेहरे पर भी झलकती।

तेल की कीमतों की बाजार से संबद्धता की नीति भी केवल जुमला साबित हुई है ।करोड़ों उभोक्ताओं क्रूड आइल की बढ़ती कीमतों के दौर में में सरकार और कंपनियों का साथ दिया है लेकिन कंपनियाँ घटती कीमतों के दौर में जनता का साथ देने से बच रहीं हैं ।जब पतली है तेल की धार तो क्यों जारी है मार!

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

वर्ल्ड वार, तुम कब आओगे?

व्यंग्य

रमेश रंजन त्रिपाठी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

प्रतिदिन सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले मोबाइल को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की अधिकृत खबर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। दरअसल, यह तमन्ना खबरों की देन है। दुनिया में चल रही तनातनी या झड़पों को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बताने में खबरें हमेशा इतनी गंभीरता बरतती हैं कि पिछले वर्ल्ड वार के बाद पैदा हुए लोगों के मन में इस महान घटना का साक्षी बनने की ख्वाहिश जाग जाना ताज्जुब की बात नहीं। जाँबाज इंसानों की आधुनिक दुनिया के इतिहास में केवल दो विश्व युद्ध होना पता नहीं अच्छी बात है या बुरी? इन दोनों लड़ाइयों के बीच केवल इक्कीस साल का फासला था। दूसरा वर्ल्ड वार खत्म हुए लगभग आठ दशक बीतने को हैं मगर कोई अंतरराष्ट्रीय झगड़ा इतना बढ़ता ही नहीं कि उसे विश्व युद्ध जैसे खिताब से नवाजा जाए। पता नहीं इसका कारण लोगों का समझदार हो जाना है या कमजोर? विज्ञान की तरक्की ने जंग में इस्तेमाल होनेवाले हथियारों को इतना एडवांस बना दिया है कि कई बार आमने-सामने डटे बिना भी प्रतिद्वंद्वी के जान-माल को भारी क्षति पहुँचाई जा सकती है। उजागर या छिपकर कई देश एटम बम भी बना रहे हैं। दोनों स्थितियों में शत्रु देश को परमाणु हथियार का भय तो होता ही होगा! लेकिन इंसान गजब का निर्दयी, जीवट और (दु)साहसी होता है। जब वह अपनी पर आ जाए तो किसी बात से नहीं डरता, न आलोचना, न बदनामी और न ही पराजय से। वह जानता है कि एक सफलता उसकी सारी बुराइयों को नेपथ्य में धकेल देगी।

जो लोग अस्सी साल के नहीं हुए हैं, उनके लिए तो दोनों वर्ल्ड वार इतिहास हैं। उन्होंने सिर्फ सुना है कि इन विश्व युद्धों में करोड़ों लोग हताहत हुए थे। दूसरे वर्ल्ड वार में एटम बम भी गिराए गए जिसमें लाखों लोग मरे और आज भी वहाँ के इंसानों में रेडियो एक्टिव दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। इस नरसंहार के रोमांच में धकेली जाती हुई दुनिया की कल्पना कितनी खतरनाक है न? पुराण बताते हैं कि पाँच हजार साल पहले मुरलीधर श्रीकृष्ण ने पांडवों और कौरवों के मध्य, उस समय के विश्व युद्ध, महाभारत को न होने देने का भरपूर प्रयास किया था लेकिन वे असफल रहे। परिणामस्वरूप लगभग सवा करोड़ लोग मारे गए। किंवदंती है कि महाबली पांडव भीम के पोते बर्बरीक ने अपने कटे सिर से उस भीषण नरसंहार को देखा था। और हाँ, संजय ने भी वेदव्यास द्वारा प्रदत्त दिव्यदृष्टि से महाभारत का आँखों देखा हाल हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। आजकल भी तो टीवी पर जंग की लाइव तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं।

विश्व युद्ध के पक्षधर और विरोधियों के अपने तर्क हो सकते हैं। ज्यादा संख्या परेशानी में पड़ जानेवालों की है लेकिन चलती है पॉवरफुल लोगों की, जो इन बहुसंख्यकों को अपने इशारों पर नचाया करते हैं। जैसे दवा बनानेवाले चाहते हैं कि लोग बीमार पड़ें तो उनका धंधा चमके, वैसे ही हथियार बनानेवाले सोचते होंगे। महंगाई, कालाबाजारी, भुखमरी के लिए जंग किसी उत्सव से कम नहीं। यह समझना आसान नहीं कि दुनिया के किसी भी कोने में चल रहे युद्ध को रुकवाने की मंशा वाले मुल्क ज्यादा होते हैं या लड़ाई चलती रहने की इच्छावाले? शांति, भाईचारा, सद्भावना, सह-अस्तित्व जैसे शब्दों के मुखौटे के पीछे अपने इरादों को छिपाने की कला में महारत हासिल करना किसी देश के कर्णधारों के लिए तपस्या से कम नहीं। और, तपस्या के बाद ही वरदान प्राप्त होता है। वरदान से मिली ताक़त का कौन कैसा इस्तेमाल करेगा, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। सोचता हूँ, खबरों को देखना कम कर दूँ, तो, शायद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका न के बराबर हो जाए। सो, भले ही हमारी पीढ़ी इस रोमांच की चश्मदीद गवाह न बन सके लेकिन आनेवाली नस्लों को इतिहास का एक अरुचिकर अध्याय और पढ़ने से राहत मिल जाएगी।

पर्यावरण

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक एवं लोक दर्शन यात्रा के संयोजक हैं।

याद आते हैं कुआं, ताल-पोखर वाले दिन

आंगन का जामुन का पेड़ कहां गया। मुझे याद आया कि बाबा के मना करने के बाद भी मैं चोरी-छिपे पेड़ पर चढ़कर काले चित्तीदार जामुन खाया करता था और एक बार डाल टूट जाने से गिरते-गिरते बचा था। अगर मेरी टूटी हुई डाल नीचे की डाल में नहीं फंसी होती तो, कल्पना मात्र से मेरी देह में सिहरन दौड़ गई। मैं खोई बिखरी स्मृतियों को समेटने में जुटा था। बाहर नीम के नीचे बने कच्चे चबूतरे का अब नामोनिशान न था एक जिसके एक ओर जानवरों के लिए लडौरी बना दी गई थीं। मेरे नाक में निंबोली और जानवरों की सानी एवं खली-भूसा की मोहक महक पसर गई थी। उस खंडहर के वीराने में एक टूटी दीवार में बैठ स्मृतियों का स्रोत कुरेदने लगा था। तो देखा कि घर के बिल्कुल सटी तलैया गायब थी। पिता जी बताया करते थे कि मकान बनाने के लिए मिट्टी खोदने से वह तलैया बनी थी जिसे हम 'डबरा' कहते थे।

जून 2024, दूसरे पखवाड़े के 5 दिन ही बीते थे। सूरज अपनी ही आग में जला जा रहा था। तीखी तेज धूप से पेड़ों की छाया भी सूख कर सिमट गई थी। अपने झुंड से बिछड़ बादल का एक छोटा टुकड़ा धूप से लुका छुपी खेलने में मशगूल था। नीरस व्याकुल शाम थके मजदूर सी घर जाने की जल्दी में थी। शहर के जलस्रोत सूख चुके थे। मेरा ध्यान अपने गांव के जल से लबालब भरे बड़े तालाब की ओर अनायास चला गया। मुझे लगा कि गांव जाकर तालाबों की वर्तमान स्थिति पर एक लेख लिखना चाहिए। हालांकि गांव बहुत दूर तो न था पर नौकरी और घर-परिवार की व्यस्तता एवं जिम्मेदारी उठाते वर्षों से गांव जाना सम्भव नहीं हो सका था। पुश्तैनी मकान अब आखिरी सांसें गिन रहा था। दैनंदिन संझवाती, दिया-बाती के अभाव में उपेक्षा के अंधेरे में घिरा मकान ढहने लगा था। लगभग डेढ़ दशक बाद मैं गांव जाने वाला था, सुबह की प्रतीक्षा थी।

उस रविवार की सुबह भी कुछ अलग न थी। गरम हवा मानो पंख बांधकर उड़ रही थी। मीठी चटनी के साथ दो परांठे और चाय उदरस्थ कर पानी की बोतल बैग में रख मैंने गांव की बस का पहला नम्बर पकड़ लिया था। बस की खुली खिड़की से आ रही हवा में शीतलता न थी। सवारियों में ज्यादातर फेरी लगाने वाले थे, दो-तीन विद्यार्थी थे और शादी-विवाह के निमंत्रण जाने वाले दो एक परिवार थे। हां, पीछे की लम्बी सीट पर बैंड बजाने वाले अपने साज लिए बैठे थे। बस में इत्र, पसीने और बीड़ी के धुएं की मिली-जुली गंध पसरी थी। मैं खिड़की के बाहर भागते पेड़ों को देखते झपकी लेने लगा था। अचानक बस के ब्रेक चरमराये और कंडक्टर मुझे झिंझोड़ते हुए बोला, बाबू जी, आपका स्टाप आ गया, यहीं उतर लें। मेरे साथ दो फेरी वाले और एक परिवार उतरा, सभी ने अपनी राह पकड़ी। मैंने बोतल निकाल गला तर किया, गमछा सर पर डाला और रजबहे (छोटी नहर) की दाहिनी पट्टी पर चलने लगा। मुख्य सड़क से सौ मीटर की दूरी पर अहीर-आरख समुदाय का पुरवा है। यहां रजबहे के ठीक बगल में एक बड़ा पक्का कुआं हुआ करता था पर अब वह मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। कभी रात के दस-ग्यारह बजे तक इस कुएं पर चहल-पहल रहा करती थी। नहाना-धोना, पशुओं को पानी पिलाना, घर के लिए पीने के पानी का यह एकमात्र स्रोत एवं सहारा था। भोर से ही पनिहारने मंगलगीत गाती अपनी-अपनी गगरियां भरने लगतीं। जगत के बाहर की ओर बनी चरही में पशुओं के लिए पानी भरा जाने लगता। भाभी देवर की हंसी-ठिठोली का गवाह बनता वह कुआं कितनी पीढ़ियों के कुआं पूजन की रस्म का साक्षी रहा है। पर अब न कुआं था, न हंसी-ठिठोली के स्वर, न कुआं पूजन की रस्म। हृदय में वेदना की लकीर खिंच गई। सौ कदम बढ़ा ही था कि ध्यान आया वहां से सौ कदम की दूरी पर जामुन का एक बड़ा पेड़ हुआ करता था जिसकी एक डाल कुछ-कुछ पालकी के बांस की तरह टेढ़ी होकर रजबहे की दूसरी पट्टी तक फैली थी। बरसात के मौसम में हम बच्चे अक्सर उस डाल से नहर के पानी में छपाक-छपाक् से कूदते थे, बंद आंखों से वह दृश्य मानो साक्षात वर्तमान हो उठा था, पर आंख खुली तो निराशा हाथ लगी, अब कोई पेड़ न था। वहां से सड़क मेरे पुरवा की ओर मुड़ी और अब मैं अपने घर-मकान के समृद्ध अतीत के खंडहर में खड़ा था। हर कमरा अटारी की दीवारें गिर चुकी थीं, बस पहचान के लिए कुछ दीवारें जमीन से सिर उठाये सांसें ले रही थीं, शायद मेरे आने की प्रतीक्षा थी उन्हें। सहसा मुझे सिसकने की आवाज सुनाई दी, मैं चारों तरफ घूम गया पर कोई न दिखा। फिर लगा कि कोई मेरी अंगुली पकड़कर खींच रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी दीवारें बोल उठीं, आने में बहुत देर कर दी बेटा, अब यहां कुछ भी शेष नहीं। क्यों आये हो, चले जाओ अपने शहर। मुझे लगा टूटी दीवारों पर मेरे बैठे पुरखे सवाल कर रहे हों, झिड़क रहे हों। मैं ख्यालों में खोया था कि तभी एक जंगली खरहा आंगन में उग आई झाडी से निकल बाहर खेत की ओर भाग गया और बबूल में बैठे बगुले पंख फड़फड़ाते उड़ गये। मेरी तंद्रा टूटी। अरे!

आंगन का जामुन का पेड़ कहां गया। मुझे याद आया कि बाबा के मना करने के बाद भी मैं चोरी-छिपे पेड़ पर चढ़कर काले चित्तीदार जामुन खाया करता था और एक बार डाल टूट जाने से गिरते-गिरते बचा था। अगर मेरी टूटी हुई डाल नीचे की डाल में नहीं फंसी होती तो, कल्पना मात्र से मेरी देह में सिहरन दौड़ गई। मैं खोई बिखरी स्मृतियों को समेटने में जुटा था। बाहर नीम के नीचे बने कच्चे चबूतरे का अब नामोनिशान न था एक जिसके एक ओर जानवरों के लिए लडौरी बना दी गई थीं। मेरे नाक में निंबोली और जानवरों की सानी एवं खली-भूसा की मोहक महक पसर गई थी। उस खंडहर के वीराने में एक टूटी दीवार में बैठ स्मृतियों का स्रोत कुरेदने लगा था। तो देखा कि घर के बिल्कुल सटी तलैया गायब थी। पिता जी बताया करते थे कि मकान बनाने के लिए मिट्टी खोदने से वह तलैया बनी थी जिसे हम 'डबरा' कहते थे। उस डबरे में बारिश का पानी भर जाता और पूरे साल गर्मियों तक काम आता। घर के बर्तन वहीं धुले जाते, पशु-पक्षी पानी पीते, सुबह भोजन हेतु चावल भी दौरी में वहीं धोये जाते। डबरा के चारों ओर कोई मेड़ न थी, खेत के बराबर ही था, बीच में गहरा और फिर ऊपर की ओर उथला होते तीन ओर से खेतों से जुड़ जाता।

एक ओर जहां हम प्रयोग करते थे, एक पत्थर की पटिया और कुछ ठोके रख दिए थे। वहीं पर कुछ अन्य पौधे भी लगाए थे। डबरा से सटी बांस की तीन कोट थीं जिस पर बारिश में अपने आप उग आए रेरुआ, लौकी, कद्दू की बेल फैल जाती और चार पांच महीने भरपूर सब्जी मिलती। बैसाख के बाद डबरा का पानी सूखकर घटने लगता। तब पशुओं के पीने के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाता। पुरवा के कुछ हम उम्र तरुण और बच्चे रजबहे से बरहा द्वारा पानी तालाब तक लाते। पाने लाने में कई दिन लगते। जल संरक्षण के प्रति यह समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती जाती। इसी डबरा के पानी से गैरी-खपरा किया जाता, आंवा को बंद करने के लिए पुआल के ऊपर लगाने के लिए गारा भी डबरा से निकालते। इस तरह हर साल डबरा साफ होकर नया रूप धारण कर लेता। डबरा के तीनों उथले हिस्सों में धान अपने आप उग आता जिसे 'पसही का धान' कहा जाता था तो पूजा और व्रत-उपवास में प्रयोग किया जाता। घर और डबरा से लगे हमारे खेत थे। धानन और गेहूं की फसलें होतीं, मेंड़ पर अरहर। हमारे खेतों के अंत की ओर एक दो-तीन बीघे का बड़ा खेत पोखर कहलाता था। उसमें देर से पकने वाली धान की बेड लगाई जाती। उसका धान लगभग मकर संक्रांति तक पकता और कटाई होती, उधर दूसरे खेतों में गेहूं बोना शुरू हो चुका होता। इस पोखर के ऊपर के बाहरी हिस्सों में गेहूं बोया जाता, अंदर का हिस्से में होली के बाद तक पानी भरा रहता। सारस और बगुले जलीय जंतुओं मछली-केकड़ा की दावत उड़ाते रहते। तब हमारे गांव में पानी का कोई संकट न था। दस हाथ खुदाई में में पानी निकल आता। फसलों की सिंचाई वर्षा आधारित थी। न खाद न कीटनाशक न ज्यादा पानी। जेठ-आषाढ में घूरे की खाद खेतों में फैला दी जाती, खेत ताकतदार बनते, मिट्टी में पानी का ठहराव अधिक रहता, खूब नमी बनी रहती। जब मैं बड़ा हुआ और अधिक पढ गया तो पोखर को दूसरे खेतों के बराबर समतल करा दिया। बाद में अपनी मूर्खता पर रोना आया कि पोखर जमीन की नमी बनाये रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण था, पक्षियों से भी नाता टूट गया। पुरवा के दूसरे डबरे पाट दिए गये, और गांव के तीनों तालाब के भीटों पर मकान उग आये हैं। आज गांव में भी पानी संकट है। ताल संस्कृति और जल देवता की आराधना के प्रति अनुराग नहीं बचा। खेत प्यासे हैं, पशु बेहाल है, पखेरू व्याकुल और हम मानव अपने सीने पर विकास का तमगा लगाए खुशी से झूम रहे हैं। पर एक सवाल मुंह बाये खड़ा है कि हम आने वाली पीढ़ी को पूर्वजों से मिली समृद्ध धरोहर सहेज कर क्यों न दे पाये? पर हम मौन हैं, अभी भी समय है, अगर चेत सके तो चेत जायें।

बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध के मायने

ऑस्ट्रेलिया की नजीर

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

लेखक वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कदम बहुत सारे लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इसकी वजहें काफी समझने लायक हैं। आज के दौर में, सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके कारण आने वाली मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों के साथ-साथ समय की बर्बादी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सोचिए, जब हम खुद सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो एक अजीब सी तुलना और असुरक्षा की भावना हमारे भीतर भी आ जाती है। अब कल्पना कीजिए कि वही प्रभाव बच्चों पर कितना गहरा असर डालता होगा, जब उनके पास इसे समझने और इससे निपटने का अनुभव नहीं होता। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उनके पूरे जीवन की नींव है। ऐसे में सोशल मीडिया के कारण उनमें असुरक्षा, चिंता, और अवसाद जैसी समस्याओं का आना सामान्य होता जा रहा है। इस प्रतिबंध से उन्हें इन चुनौतियों से दूर रखने का एक मौका मिलेगा।

सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से बच्चों का असली दुनिया से जुड़ाव कमजोर होता जा रहा है। वह समय जो वह खेल-कूद, दोस्तों के साथ या परिवार के साथ बिता सकते हैं, वह स्क्रीन के सामने खत्म हो जाता है। असली रिश्तों से जुड़ाव और बातचीत का अनुभव उन्हें आत्मविश्वास और बेहतर सामाजिक कौशल देता है। अगर उन्हें सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखा जाए, तो शायद वह ज्यादा स्वस्थ तरीके से असली दुनिया से जुड़ पाएंगे।

बच्चों को अक्सर सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्म-सम्मान और मानसिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित होती है। साइबर बुलिंग के कारण बच्चे अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं और उनमें डर, चिंता और अवसाद बढ़ सकता है। यह प्रतिबंध बच्चों को इन खतरों से बचाने में सहायक हो सकता है, जिससे वे सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकेंगे।

सोशल मीडिया बच्चों के समय को अनजाने में ही निगल जाता है। वे अक्सर बिना किसी खास मकसद के वीडियो देखते रहते हैं, पोस्ट्स स्क्रॉल करते हैं और चैट में घंटों बिता देते हैं। यह समय जो उनके पढ़ाई, खेल, और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में खर्च हो सकता था, वह बर्बाद हो जाता है। समय की इस बर्बादी के कारण उनका ध्यान बंट जाता है, और वे महत्वपूर्ण कार्यों में एकाग्रता नहीं रख पाते। सोशल मीडिया से दूरी उन्हें समय का सदुपयोग करने की आदत सिखा सकती है और उनकी प्रगति में मददगार हो सकती है। बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध के साथ ही माता-पिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह ज़रूरी है कि माता-पिता बच्चों को यह समझाएं कि सोशल मीडिया के बिना भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उन्हें सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराएं। बच्चों के समय का सदुपयोग कैसे करें, यह सिखाना भी माता-पिता की जिम्मेदारी है ताकि बच्चों का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके।

यह सवाल बहुत स्वाभाविक है कि क्या यह कदम हमारे देश में भी उठाया जाना चाहिए। भारत में सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ा है और यहां भी बच्चों को साइबर बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम इस दिशा में ध्यान दें और बच्चों को सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें, तो हो सकता है कि हम एक बेहतर और संतुलित पीढ़ी का निर्माण कर पाएं।

कुल मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया का यह निर्णय बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, समय प्रबंधन और उनके भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है। सोशल मीडिया के प्रति हमारी बढ़ती निर्भरता पर थोड़ा नियंत्रण रखना शायद हमारे समाज के लिए भी फायदेमंद साबित हो। बच्चों के लिए यह एक मौका है कि वे असली दुनिया से जुड़ें, सीखें, और जीवन के वास्तविक अनुभवों को महसूस करें। एक मनोचिकित्सक के रूप में, मुझे लगता है कि बच्चों को स्वस्थ और सकारात्मक माहौल देना ही उनकी सच्ची परवरिश का हिस्सा है, और अगर इस कदम से उनका बचपन खुशहाल हो सकता है, तो यह निर्णय स्वागत योग्य है।

बिहार का बनगांव

संदीप कुलश्रेष्ठ

साम्प्रदायिक सौहार्द्र का अनुपम उदाहरण

बिहार के सहरसा जिले की नगर पंचायत बनगाँव में 133 साल से हर रविवार विभिन्न धर्मों की धर्म सभा आयोजित होती है। इस गाँव के करीब 20 हजार हिन्दू अपने नाम के साथ खां उपनाम लगाते है। बोलचाल में भी उसका उपयोग होता है। दिवाली, जन्माष्टमी और होली जैसे बड़े त्यौहारों के कर्ताधर्ता मुस्लिम ही होते हैं। इस प्रकार यह गाँव देश में साम्प्रदायिक सद्भाव का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

इस नगर पंचायत बनगाँव के कई गाँवों में 15 से 20 हजार हिन्दू अपने नाम में खां लगाते हैं। इस गांव में मिश्र, झा, चौधरी आदि उपनाम लगाने वाले भी हैं। पर सबसे ज्यादा उपनाम खां ही लगाते हैं। जैसे भोलानाथ खां, शंकर खां, हेमचन्द्र खां, अरविन्द खां आदि। यहाँ भोलानाथ खां रिटायर्ड शिक्षक है, शंकर खां किसान है, हेमचन्द्र खां स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड है, अरविन्द खां बोकारो में व्यवसाय करते थे, अब गांव में ही रहते है आदि।

उक्त नाम सुनकर हर कोई चौंक जाता है। जब ये लोग गाँव से बाहर शहरों में जाते है, तब भी लोग ऐसे ही चौंक जाते है। किन्तु ये सहज रहते हैं। उन्होंने इसे आत्मसात कर लिया है।

यहाँ के लोग मानते है कि उनके पुरखों ने मुगलकाल में अपने नाम के साथ खां उपनाम लगाना शुरू किया था। इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित है। लेकिन सही वजह कोई नहीं जानता। कई किताबों में भी हिन्दुओं के खां उपनाम होने का जिक्र है। यहाँ अनेक पीढ़ियों से होली, दीपावली, जन्माष्टमी जैसे हिन्दू त्यौहारों में मुख्य कर्ता-धर्ता मुस्लिम ही होते हैं।

इस गाँव में 133 साल से हर रविवार को धर्मसभा होती है। इसमें सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते है। बताया जाता है कि इसकी शुरूआत मिथिलांचल के संत कवि लक्ष्मीनाथ गोस्वामी ने की थी। यह अपने आप में देश में अकेला विलक्षण उदाहरण है।

हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर इस गाँव में भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी मुस्लिम परिवार के ही लोग लेकर आते हैं। इस बनगाँव में अलग-अलग गौत्र के लोग एक ही गाँव में रहते है। इसलिए बेटे-बेटियों की शादी गाँव में ही कर देते है। इस प्रकार साम्प्रदायिक सद्भाव की यह परंपरा लगातार चल रही है।

देश में साम्प्रदायिक सद्भाव की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिए देशभर के गाँवों और शहरों को इस बनगांव से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर विभिन्न त्यौहार मनाते हैं। ये अपने आप में अनुपम उदाहरण है ही। हिन्दूओं के प्रमुख त्यौहारों के कर्ता-धर्ता भी मुस्लिम होते हैं, यह भी प्रेरणास्पद है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 133 साल से बनगांव में धर्म सभा नियमित रूप से आयोजित हो रही है। इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है।

सेहत

प्रियंका सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

बच्चों में स्क्रीन की बढ़ती लत एक गंभीर समस्या

महामारी के बाद भारत में बच्चों के लिए स्क्रीन का समय काफ़ी बढ़ गया है, उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास पर इसके प्रभावों के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं, जिससे संतुलित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अत्यधिक स्क्रीन समय आमने-सामने की बातचीत को कम करता है, जिससे सामाजिक कौशल विकास में बाधा आती है। 2024 के अध्ययन में पाया गया कि प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक स्क्रीन समय वाले बच्चों में सामाजिक जुड़ाव का स्तर कम था। स्क्रीन अक्सर पारिवारिक बातचीत की जगह ले लेती है, जिससे पारिवारिक सामंजस्य और साझा अनुभव कम हो जाते हैं। परिवारों को भोजन और बातचीत जैसी गतिविधियों पर कम समय बिताते हुए देखा जाता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव प्रभावित होता है। डिजिटल इंटरैक्शन पर तेजी से निर्भर बच्चे व्यक्तिगत सामाजिक संकेतों और रिश्तों के साथ संघर्ष कर सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि किशोरों में उच्च स्क्रीन समय भावनात्मक विनियमन में देरी से सम्बंधित है। स्क्रीन की लत शारीरिक गतिविधियों में बिताए गए समय को सीमित करती है, जिससे गतिहीन व्यवहार होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट में शहरी बच्चों में बाहरी गतिविधियों में 40 प्रतिशत की कमी को दर्शाया गया है।

स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताना बच्चों में चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है। लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ (2024) ने 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर समय बिताने वाले किशोरों में चिंता के लक्षणों में 15 प्रतिशत की वृद्धि पाई। तेज़ गति वाली डिजिटल सामग्री के लंबे समय तक संपर्क में रहने से ध्यान अवधि और एकाग्रता के स्तर में कमी आ सकती है।

एम्स दिल्ली (2023) द्वारा किए गए अध्ययन बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन उपयोग को एडीएचडी जैसे लक्षणों से जोड़ते हैं। स्क्रीन लाइट के संपर्क में आने से नींद के चक्र प्रभावित होते हैं, जिससे नींद पूरी नहीं होती और संज्ञानात्मक कार्य कम होता है। इंडियन जर्नल ऑफ़ पीडियाट्रिक्स द्वारा 2023 में किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग करने वाले 60त्न बच्चों की नींद का पैटर्न गड़बड़ा गया था। सोशल मीडिया का उपयोग अक्सर आत्म-सम्मान को प्रभावित करता है, खासकर किशोरों में, अवास्तविक तुलना और साइबरबुलिंग के कारण। भारतीय किशोर अत्यधिक सोशल मीडिया एक्सपोजर से आत्म-सम्मान सम्बंधी समस्याओं का अनुभव करते हैं।

स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे तकनीक के इस्तेमाल के मामले में सीमाएँ तय करें। यहाँ एक विशेषज्ञ गाइड है जो आपको बताती है कि कैसे स्क्रीन की लत में पदार्थों के समान ही तंत्र होता है, जो डोपामाइन में समान

वृद्धि पैदा करता है। स्क्रीन के उपयोग में लगातार वृद्धि के साथ, मस्तिष्क के सर्किट अनुकूल हो जाते हैं और डोपामाइन के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। नतीजतन, आप जो देखते हैं वह समान आनंद का अनुभव करने के लिए अधिक उपभोग करने की बढ़ती आवश्यकता है। एक आम ग़लतफ़हमी यह है कि लत एक विकल्प या नैतिक समस्या है। सच्चाई इससे ज़्यादा दूर हो ही नहीं सकती। एक निश्चित बिंदु के बाद, लत एक जैविक समस्या बन जाती है जिसका शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। माता-पिता के लिए हस्तक्षेप करने, सही व्यवहार का मॉडल बनाने और अपने बच्चों को जीवन कौशल के रूप में स्क्रीन प्रबंधन सिखाने की स्पष्ट आवश्यकता है।

माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम को प्रबंधित करने और स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों से लैस करें। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने माता-पिता के लिए डिजिटल प्रबंधन पर कार्यशालाओं की सिफ़ारिश की है।

कम उम्र से ही स्क्रीन का जिम्मेदाराना उपयोग सिखाने के लिए पाठ्यक्रम में डिजिटल वेलबीइंग को शामिल करें। दिल्ली सरकार ने चुनिंदा स्कूलों में डिजिटल साक्षरता सत्र शुरू किए हैं।

ायु के आधार पर आधिकारिक स्क्रीन टाइम दिशा-निर्देश विकसित करें और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से उनका प्रचार करें। WHO दिशा-निर्देश विकासात्मक चरणों के आधार पर स्क्रीन टाइम प्रतिबंधों का सुझाव देते हैं। स्वस्थ सामाजिक संपर्क के साथ डिजिटल उपभोग को संतुलित करने के लिए बाहरी और समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। खेलो इंडिया पहल बच्चों में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देती है, जिससे स्क्रीन टाइम में अप्रत्यक्ष रूप से कमी आती है। स्कूलों और समुदायों में तकनीक-मुक्त क्षेत्रों और डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करें। कुछ स्कूलों ने बच्चों को गैर-डिजिटल गतिविधियों में शामिल होने में मदद करने के लिए 'स्क्रीन-फ्री डेज़' शुरू किए हैं।

स्क्रीन टाइम के प्रभावी प्रबंधन के लिए परिवारों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं को शामिल करते हुए बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगली पीढ़ी के समग्र विकास के लिए संतुलित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा, जिससे एक लचीले और समग्र समाज का निर्माण होगा।

स्क्रीन की लत एक वास्तविक समस्या है जो महामारी के कारण और भी बढ़ गई है और वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित कर रही है। माता-पिता को अपने बच्चे के स्क्रीन उपयोग के पैटर्न के प्रति सतर्क, सक्रिय और संलग्न रहने की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की खोज करना और अपने बच्चे की दुनिया के बारे में जानकारी रखना आपको अपनी आशंकाओं के बारे में उनसे बात करने के लिए बेहतर भाषा दे सकता है। सीमाएँ निर्धारित करना अल्पावधि में कठिन लग सकता है लेकिन दीर्घावधि में यह बहुत लाभदायक होगा।

श्याम पटेल (प्रिंस) का निधन, तेरहवीं कार्यक्रम 16 को

बैतूल। समाजसेवी श्याम कुमार पटेल (प्रिंस) का विगत 4 नवंबर को आकस्मिक निधन हो गया। जिनकी त्राता कार्यक्रम 6 नवंबर को नर्मदापुरम होशंगाबाद में संपन्न हुआ, वहीं तेरव्हीं कार्यक्रम 16 नवंबर शनिवार को निज निवास मलकापुर में रखा गया है। शोकाकुल परिवार वाजबहादूर वर्मा, राजबहादूर वर्मा, नर्मदा प्रसाद, नगेन्द्र चौधरी, विजेंद्र चौधरी एवं हंस कुमार चौधरी ने सभी परिचितों से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

पावरझंडा में भाजपा की संगठनात्मक चुनाव को लेकर बैठक संपन्न

शाहपुर। भाजपा शाहपुर मंडल की गुरुवार को संगठनात्मक चुनाव-2024 को लेकर बैठक ग्राम पावरझंडा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके ने की। जिला से आए मंडल संगठन पर्व के सहयोगी श्री अतित पवार एवं भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष सतिष मिश्रा ने बुथ पर चर्चा की। विधायक श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जो कि संगठन पर्व के पश्चात ही संगठन के विभिन्न पदों पर पदाधिकारी नियुक्ति करती है। संगठन पर्व प्रभारी अतित पवार ने कहा, कि पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का समान अधिकार है और जो भी पार्टी हाई कमान का निर्णय होगा। उसी के अनुसार जिले में संगठन के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बैठक में मंडल के सभी पदाधिकारी,और कार्यकर्ता गण मौजूद थे।

कन्या उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित की गई प्रदर्शनी

शाहपुर। कन्या उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी, गणित विज्ञान प्रदर्शनी संगोष्ठी आदि का आयोजन किया गया। संकुल प्राचार्य वीरेंद्र कुमार नामदेव ने बताया कि शासन के नियम अनुसार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी संकुल स्तर पर संकुल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के बच्चों के द्वारा लगाई गई है। प्रदर्शनी से लोगों में किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी अत्यंत जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्र-छात्राओं के शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। लोगों को जिस चीज का वह उपयोग करते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी अवश्य होना चाहिए। छात्र-छात्राओं में भी इस प्रदर्शनी और संगोष्ठी को लेकर बहुत उत्साह और शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्रों के उत्साह वर्धन को सहयोग कर बढ़ाया।

किराड़ समाज के दीपावली मिलन में लिया नशा मुक्ति का संकल्प

बैतूल। अखिल भारतीय किराड़ महासभा के पदाधिकारियों ने उत्साह के साथ भगवान बलराम की पूजा अर्चना कर दीपावली मिलन धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में स्थानीय पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सेवानिवृत्त तहसीलदार व उपाध्यक्ष डीएस पटेल ने कहा कि आज के समय में गांव में युवाओं का नशे की ओर झुकाव हो रहा है। यह परिवार ही नहीं बल्कि समाज व राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी क्षति है। हम सभी को आगे आकर जनजाग्रति लाकर नशा मुक्त गांव व समाज बनाने के लिए लोगो को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की महत्ती आवश्यकता है। दीपावली मिलन के अवसर पर सामाजिक पदाधिकारियों ने अनेक सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। इस मौके पर महासभा के जिला अध्यक्ष दयाल पटेल हारोड़े, उपाध्यक्ष डीएस पटेल, नवयुवक जिला अध्यक्ष मदनलाल डढोरे, नीलकंठ लिल्होरे, रामदास हारोड़े, धनराज नरवरे, मनोहर लिल्होरे, धनराज डढोरे, आरके लिल्होरे, मगरध्वज सूर्यवंशी आदि ने बैठक को संबोधित किया।

ट्रेन से कटी मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश

बैतूल। बैतूल-नागपुर रेल लाइन पर मलकापुर के पास एक व्यक्ति का ट्रेन से कटा शव मिला है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। मृतक को जिला अस्पताल बैतूल लाया गया है। घटना की जांच कर रहे उप निरीक्षक उमेश बिल्लौरे ने बताया कि रेलवे से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लाइट इंजन से रन ओवर हो गया है। इस सूचना पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा है। फिलहाल उसके पास पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला है। वह सफेद कुर्ता पहने हुए है। इधर पुलिस को आशंका है कि व्यक्ति रन ओवर यानी टकराने से नहीं बल्कि किसी ट्रेन से गिरकर मरा होगा। फिलहाल इन दोनों बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

टिप्पर वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली में ऊपर तक भरा जा रहा कचरा, सड़क पर गिरने से फैल रही गंदगी

अनदेखी : खुले वाहनों में परिवहन हो रहा कचरा, सड़क पर गिरने से संक्रमण फैलने का खतरा

संजय द्विवेदी, बैतूल। शहर में निकलने वाले कचरे को खुले वाहनों (टिप्पर और ट्रैक्टर-ट्रॉली) में परिवहन तक ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों टन कचरा खुले वाहनों में शहर की सडक़ों से होकर गुजरता है। इससे वायु प्रदूषित तो होती ही है, साथ ही इस लापरवाही का खामियाजा आमजनता को स्वास्थ्य के साथ समझौता कर चुकाना पड़ता है। खासबात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हर प्रकार के कचरे के निपटान के लिए गाइड लाइन निर्धारित कर रखी है। जिसमें कचरे के परिवहन से लेकर नष्ट करने के नियम भी बनाए गए है, लेकिन इन गाइड लाइन का पालन शहर में नहीं हो रहा। दरअसल शहर के 33 वार्डो से कचरा कलेक्शन के लिए नगरपालिका के पास टिप्पर वाहन मौजूद है। इन वाहनों से नगरपालिका डोर-टू-डोर गीला-सूखा कचरा कलेक्ट करती है। शेष जहां-तहां पड़े कचरे और नालियों का मलबा उठाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। नगरपालिका के टिप्पर वाहन में ढक्कन है, लेकिन चालक फिर भी ढक्कन नहीं लगाते, वहीं इन वाहनों में क्षमता से अधिक कचरा भरकर ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है। इस दौरान यह कचरा सडक़ों पर गिरता है। ऊपर से वाहन खुले होने के कारण जब यह गाडियां सडक़ों से गुजरती है तो तेज दुर्गंध उठती है। जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सड़क पर गिरता है कचरा, दुर्गंध से लोग परेशान

खुले वाहनों में कचरा परिवहन करने से सडक़ों पर गंदगी और वातावरण में दुर्गंध फैलती है। कचरा परिवहन के दौरान गीले कचरे से पानी रिसता है, जो संक्रमण बीमारियों को जन्म देने में सहायक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं काफी दिनों तक कचरा पड़े होने के कारण लोगों को परिवहन के दौरान दुर्गंध का भी सामना करना होता है। बता दे कि नगरपालिका गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा एकत्रित करती है। यहां तक कचरा पहुंचाने के लिए कचरा वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली शहर की गलियों से होकर गुजरती है। इस दौरान वाहनों से कचरा सडक़ पर गिरता है। गौठाना रोड पर अक्सर ऐसी स्थिति देखी जा सकती है, जब कचरा, वाहनों से गिरकर सडक़ पर पड़ा नजर आता है।

कर्मचारियों बिना सुरक्षा उपकरण करते हैं साफ-सफाई

गलियों की साफ-सफाई और नालों को गंदगी से मुक्त कराने वाले कर्मचारियों के पास सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण तक नहीं है। अक्सर नपा कर्मचारी बिना दस्ताने, लॉन बूट और मास्क पहने सफाई का कार्य करते नजर आते है। जिससे कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ सकते है। इस संबंध में चिकित्सकों की माने तो लंबे समय तक पड़े कचरे को बिना सुरक्षा उपकरण के साफ किया जाए तो कर्मचारियों को खुजली, चमड़ी का रोग, संक्रमण जैसी बीमारियां हो सकती है, लेकिन इस दिशा में भी नगरपालिका अधिकारियों का विशेष ध्यान नहीं है या नपा अधिकारियों ने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के लिए पाबंद करने सख्त निर्देश तक नहीं दिये है।

इनका कहना है -

टिप्पर वाहन में ढक्कन है, लेकिन चालक लापरवाही करते है। ट्रैक्टर वालों को भी तिरपाल दिया है, परंतु चालक तिरपाल नहीं डालते है। काम की अधिकता भी रहती है। फिर भी हम निर्देश देगे कि कचरा वाहन के ढक्कन लगाकर ही कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाये।

- संतोष धनेलिया, स्वच्छता निरीक्षक, नगरपालिका बैतूल

खुले में कचरा परिवहन से वायु प्रदूषण

खुले में कचरा परिवहन, न सिर्फ सडक़ पर गंदगी फैलाने का कारण बन रहे है, बल्कि यह व्यवस्था वायु प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रही है। खासकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में नालियों का मलबा भरकर परिवहन किये जाने के दौरान पानी सडक़ पर रिसता है, जो लोगों को संक्रमित कर सकता है। खुले में कचरा परिवहन के दौरान कचरे से उठने वाली दुर्गंध के कारण सडक़ पर चलने वाले लोगों को नाक पर रूमाल रखकर चलना पड़ता है। जानकार बताते है कि कचरा परिवहन के लिए लीकप्रुफ वाहनों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन नगरपालिका रिहायसी क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर और खुले वाहनों में कचरे का परिवहन कर रहा है।

दक्षिण वनमंडल ने 33 युवाओं को प्रशिक्षण देकर बनाया आत्मनिर्भर

- कंप्यूटर ऑपरेटर और स्पोकन इंग्लिश का 45 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया
- 25 युवाओं को कंपनी में मिली प्लेसमेंट

बैतूल। दक्षिण वनमंडल द्वारा ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य से एक सराहनीय कदम उठाया गया है। वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में ग्राम वन समिति के 33 युवाओं को कंप्यूटर ऑपरेटर और स्पोकन इंग्लिश का 45 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण वन विद्यालय बैतूल में दिया गया, जो 16 जुलाई से 6 सितंबर 2024 तक चला।

इस पहल के माध्यम से वनमंडल ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। प्रशिक्षण के बाद वर्धमान फेब्रिक कंपनी मंडीदीप, भोपाल से समन्वय स्थापित कर 25 प्रशिक्षित युवाओं को 7 नवंबर 2024 को प्लेसमेंट भी दिलवाया गया। इन युवाओं को कंपनी में प्रतिमाह 12 हजार से 18 हजार रुपये का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा, 8 अन्य युवा अपना स्वयं का स्वरोजगार प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पहल में उपवनमंडलाधिकारी और वन परिक्षेत्राधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दक्षिण बैतूल वनमंडल द्वारा पूर्व में भी ग्राम वन समिति के सदस्यों का कौशल उन्नयन किया गया है, जिसके तहत 390 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणपत्र दिए गए। वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को वन विकास से ग्राम विकास थीम पर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और वनों को संरक्षित करने के अलावा अधोसंरचना विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। अब तक 145 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट मिल चुकी है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

153 स्कूलों में बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित

वर्ष 2021 से जारी है स्कूलों में शैक्षणिक सामग्री बांटने का अभियान

बैतूल। शासकीय माध्यमिक शाला सिमोरी में गुरुवार को समाजसेवी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े रमेश भाटिया के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में शैक्षिक विकास और देशप्रेम की भावना का संचार करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रमेश भाटिया, समाजसेवी सुखदेव नारे, रक्तवीर पिंकी भाटिया, समाजसेवी सुरेन्द्र पंडाग्रे और शिक्षक मारोतिराव चौकीकर उपस्थित रहे। अभियान स्कूल स्कूल जाना है, विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री फ्री दिलाना है के अंतर्गत अब तक 153 स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त में रबर, पेंसिल, ड्राइंग कॉपी, रफ कॉपी, कलर सेट, पानी की बॉटल, मिठाई, चॉकलेट और भारत माता की फोटो बांटी जा चुकी हैं। गुरुवार को इस अभियान के तहत सिमोरी स्कूल में भी यही सामग्री बच्चों को दी गई। कार्यक्रम के दौरान रमेश भाटिया ने बच्चों को जातिगत भावना से ऊपर उठकर देशहित की भावना को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। उन्होंने अपने पिता द्वारा बताई गई स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी सुनाई, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को भावुक कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूल स्कूल जाना है अभियान का उद्देश्य बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ाना और उनके विशेष कौशल का विकास करना है। समाजसेवी सुखदेव नारे ने विद्यालय के अनुशासन और परिसर की सराहना की। कार्यक्रम में शैलेंद्र बिहारिया, ममता गोहर और राधिका पटैया भी मौजूद रहे। सभी ने इस विशेष पहल की सराहना की और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

गौवंश परिवहन की सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रक की घेराबंदी की, लेकिन निकली बकरियां

बैतूल। गौवंश परिवहन की सूचना पर पुलिस ने ट्रक की घेराबंदी की, लेकिन ट्रक में गौवंश न होकर बकरियों को ले जाया जा रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में अवैध रूप से गौवंश का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर चौकी प्रभारी पांढर उपनिरीक्षक दिनेश कुमरे एवं चौकी प्रभारी सोनाघाटी वहीद खान के साथ पुलिस टीम उपनिरीक्षक नरेंद्र उइके, उपनिरीक्षक पंचम उइके एवं अन्य स्टाफ ने चेकिंग अभियान चलाया। मुखबिर द्वारा बताए गए वाहन क्रमांक एमपी 09, जेजी 8666 को हाईवे पर रुकवाकर तलाशी ली गई, जिसमें गौवंश न होकर बकरियों को ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान दो वाहनों से 600 रुपये का समन शुल्क वसूला गया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला बाल संरक्षण का प्रशिक्षण

बाल विवाह और तस्करी रोकथाम की कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई शामिल

बैतूल। प्रदीपन संस्था द्वारा बाल तस्करी और बाल विवाह रोकथाम के लिए वन विद्यालय सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में जिले की 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश शुभम नीमा, जिला विधिक सेवा सलाहकार सोमनाथ राय, एडिशनल एसपी कमला जोशी, और पीएलवी उपस्थित रहे। संस्था की डायरेक्टर श्रीमती रेखा गुजरे ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जिले में बालिकाओं और महिलाओं के अपहरण एवं तस्करी की घटनाओं को रोकना जरूरी है। जिला विधिक सेवा सलाहकार सोमनाथ राय ने विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं के निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधानों की जानकारी दी। एडिशनल एसपी कमला जोशी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे गांवों में पलायन कर रहे परिवारों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार करने के लिए प्रेरित करें और बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस को सूचित करने का आग्रह किया। संस्था की काउंसलर दीपमाला खातरकर ने मानव तस्करी के कारणों और उसके दुष्परिणामों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रोजगार हेतु पलायन करने वालों का पंचायत में पंजीकरण होना चाहिए ताकि शोषण की स्थिति में उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सके। चारू वर्मा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह के दुष्परिणामों और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने देवउठनी ग्यारस के बाद विवाह आयोजनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई और बाल संरक्षण समिति की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। कार्यशाला के अंत में बाल विवाह के खिलाफ सभी ने शपथ ली। कार्यक्रम का समापन विशाल आर्य और पुनम अतुलकर ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त कर किया।

विद्या भारती का 5 दिवसीय नेतृत्व विकास शिविर

मां रेवा के तट नेमावर में प्रांतीय संगठन मंत्री निखलेश माहेश्वरी ने कहा शिविर से होगा भैया बहनों का समग्र विकास

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। विद्याभारती के मार्गदर्शन में सरस्वती शिशु मंदिरों के भैया-बहिनों के समग्र विकास के लिए कई गतिविधियों के क्रम में गत वर्ष से समग्र विकास योजना प्रारम्भ की गई है। इसी क्रम में आज 5 दिवसीय नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर की योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 के चयनित भैया-बहिनों के विद्यालय, विभाग एवं प्रान्त स्तरीय शिविर आयोजित होंगे। कक्षा 9-10 के भैया-बहिनों के लिए विद्यालय स्तर पर त्रिदिवसीय दिशा बोध शिविर , कक्षा 11 के भैया-बहिनों के लिए पांच दिवसीय नेतृत्व विकास शिविर एवं कक्षा 12 के भैया-बहिनों के लिए प्रान्तीय स्तर पर एक दिवसीय अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त उद्गार प्रांतीय संगठन मंत्री निखलेश माहेश्वरी ने नेतृत्व विकास शिविर वर्ग समीपस्थ श्री दिगम्बर जैन रेवातट सिद्धोदय सिद्धक्षेत्र, नेमावर में कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कहें। इस अवसर पर ग्रामीण शिक्षा के प्रान्त प्रमुख चंद्रहंस पाठक , सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान प्रांतीय समिति सदस्य संदीप केकरे, विभाग समन्वयक रामकुमार व्यास एवं विद्या भारती पूर्व छात्र एवं हरदा नगर बाल विकास

समिति, सचिव आलोक जैन आदि उपस्थित थे। श्री माहेश्वरी ने नेतृत्व विकास शिविर के उद्देश्यों पर विस्तार से सारगर्भित प्रकाश डालते कहा कि ऐसे शिविरों से सरस्वती शिशु मंदिर के भैया, बहनों का उत्तरोत्तर विकास की वृद्धि होगी। इसके पूर्व मंचस्थ अतिथियों ने विद्या दायिनी मां सरस्वती,प्रणवाक्षर ऊं एवं भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्जवलित किया। अतिथि परिचय एवं स्वागत विभाग समन्वयक रामकुमार व्यास ने किया। आपने नेतृत्व विकास शिविर आयोजन के लक्ष्य पर अपनी बात रखी। नेतृत्व विकास शिविर संयोजक बसंत पटेल ने बताया कि नर्मदापुरम् विभाग के नर्मदापुरम्, बैतूल एवं हरदा जिले के करीबन 100 से अधिक भैया-बहिन संरक्षक आचार्यों सहित सहभागिता कर रहे हैं। शिविर का संचालन वरिष्ठ प्राचार्य अशोक कुमार दुबे ने किया। नेतृत्व विकास शिविर बृजबिहारी त्रिपाठी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

सेंट्रल बैंक द्वारा पेंशनरों हेतु डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान प्रारंभ

भोपाल, नप्र। भोपाल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 3.0 का आयोजन किया गया। यह अभियान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। इस अभियान के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने में सहूलियत प्रदान कर रहा है, जिससे उनकी सेवा में और भी अधिक पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

देश भर में शासकीय सेवानिवृत पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू इस योजना के अंतर्गत अब सभी रिटायर्ड पेंशन भोगी इसका लाभ ले सकेंगे।

राजधानी भोपाल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया टी टी नगर न्यू मार्केट शाखा में पेंशनर शिविर का आयोजन किया गया 6 नवंबर से राष्ट्रव्यापी स्तर पर संचालित इस शिविर का शुभारंभ नई दिल्ली पहुंची पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली की अपर सचिव श्रीमती सोनिका खट्टर द्वारा किया गया। इस अवसर पर एस एलबी सी महा प्रबंधक तरसेम सिंह जीरा, दर्शन सिंह डिगरा उप क्षेत्र प्रमुख भोपाल, शाखा प्रबंधक मृगनयनी चौहान, मनीष कुलकर्णी, रजनीश पाटीदार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण एवं पेंशनभोगी जन उपस्थित रहे।

इस दौरान इस अधिकारीयों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 2.0 की सफलता के बाद 3.0 को भव्य रूप से लागू किया गया है। गत वर्ष इस अभियान ने 70 लाख का लक्ष्य पूर्ण किया था। जबकि इस बार 2 करोड़ रखा गया है।

केंद्र सरकार के इस योजना की जानकारी देते हुए अधिकारी बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर प्रत्येक आवेदक का फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक उपयोग किया गया है। जिसके माध्यम से अब कोई भी पेंशनभोगी किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन से अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता हैं।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 1 से 30 नवंबर, 2024 तक आयोजित कैपेनिंग कार्यक्रम में देशभर के 800 शहरों/जिलों में जन जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। जिस दूरदराज क्षेत्रों के पेंशन भोगी जानों को सुविधा का लाभ मिल सके। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के के द्वारा भोपाल शहर में पांच स्थानों पर टीटी नगर शाखा अरेरा हिल्स शाखा, गुलमोहर कॉलोनी शाखा, साकेत नगर शाखा एवं अरेरा कॉलोनी शाखा के माध्यम से उक्त डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र कैंपेन हेतु विशेष कैंप लगाए गए थे तथा आज दिनांक को 570 डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करवाए गए. इस कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में पेंशनभोगी शामिल हुए। बैंक ने इस कार्यक्रम में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया और पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रक्रिया के लाभों से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन विजय बांक द्वारा किया गया इस अवसर पर पेंशनरों हेतु निःशुल्क स्वास्थ शिविर का भी आयोजन किया गया

आमला विधानसभा में 26 लाख से होंगे विभिन्न निर्माण कार्य

बैतूल। आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे की स्वेच्छानुदान निधि से आमला जनपद पंचायत के ग्रामों में 26 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत तरोडाकला के ग्राम कचरबोह में रूपलाल यादव के घर के पास 5 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत रमली में श्मशान घाट में बैठक हेतु सीढ़ी सहित शेड निर्माण कार्य 3 लाख 50 हजार रुपए की लागत से होगा। आमला जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मालेगांव में 3 लाख 50 हजार रुपए की लागत से धनाराम साहू के घर से पंचायत भवन की ओर 104 मीटर लंबी सीमेंट कांक्रीट सडक़ का निमार्ण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत परसोडी में अनिल के घर से लखन के घर की ओर 2 लाख 50 हजार रुपए की लागत से 83 मीटर लंबी सीसी रोड निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत डेहरी के ग्राम मांडई में नागदेव रोड से दिलीप यदुवंशी के घर तक 4 लाख 50 हजार रुपए लागत से 149 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सडक़ निमार्ण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत रतेडाकला में राजेश यादव के घर के पास 2 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक मंच निमार्ण कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मालेगांव के ग्राम बासन्या में ढीमर मोहल्ले में 2 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य होगा। ग्राम पंचायत बोरी खुर्द में अजा मोहल्ले के पास 3 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक मंच निमार्ण कार्य किया जाएगा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत तरोडाकला, रमली, मालेगांव, परसोडी, रतेडाकला, बोरीखुर्द, मालेगांव तथा ग्राम पंचायत डेहरी को योजना के तहत निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

छात्राओं का डिमांस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल में शैक्षिणिक भ्रमण

भोपाल। संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में वाणिज्य विभाग द्वारा रिटेल मैनेजमेंट के क्षेत्र में व्यावहारिक और प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, बी.बी.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए एक शैक्षणिक विजिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रिटेल मैनेजमेंट के मूल सिद्धांतों के साथ-साथ उद्योग विशेषज्ञों द्वारा दी गई अद्यतन जानकारियां भी शामिल की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को विषयानुसार कौशल प्रदान करना था, जो आधुनिक रिटेल उद्योग की मांगों के अनुसार है। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.डालिमा पारवानी ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण छात्राओं में विषय के प्रति गहरी समझ एवं अंतर्दृष्टि विकसित करने और भविष्य में अच्छे पेशेवर बनने के लिए तैयार करते हैं। इस पहल के माध्यम से छात्राओं को रिटेल उद्योग में आधुनिक तरीके और तकनीकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस विजिट में विशेष रूप से छात्राओं ने रिटेल उद्योग में प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांतों, रिटेल सॉफ्टवेयर एवं तकनीक, नवीनतम तकनीकी उपकरणों तथा सॉफ्टवेयर के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की जिससे वे डिजिटल युग के साथ कदम मिलाकर चल सकें। इसके साथ ही ग्राहक व्यवहार और खरीदारी के पैटर्न का ज्ञान, ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में जाना। इन्वेंटरी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में छात्राओं को सही समय पर उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के तरीके सिखाए गये और डेटा-चालित का प्रयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में डेटा का महत्व और उसका उपयोग भी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस विजिट में लगभग 40 छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम की सफलता पर महाविद्यालय प्रबंधन ने वाणिज्य विभाग को बधाई दी।

ताऊ-ताई की प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने लगाई थी फांसी, प्रकरण दर्ज

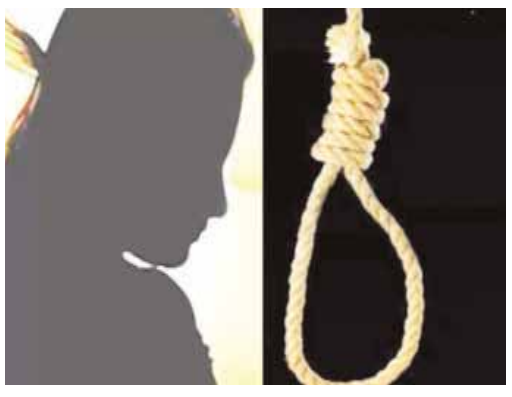

भोपाल निप्र। शहर के चूनाभट्टी इलाके में स्थित दुर्गानगर में 19 वर्षीय छात्रा द्वारा खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने नौ महीने की जांच के बाद युवती के ताऊ और ताई को आरोपित बनाया है। दोनों आरोपित पलक को घर के काम न करने पर प्रताड़ित करते थे। साथ ही उसे तरह-तरह के ताने देते थे, जिससे तंग आकर उसने इसी वर्ष फरवरी माह में खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चूनाभट्टी थाना पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय पलक सोंधिया अपने ताऊ-ताई के साथ रहती थी। ताऊ आनंद सोंधिया चार इमली में काम करता है, जबकि उसकी ताई ममता सोंधिया बंगलों में खाना बनाने का काम करती है। उनके भी दो बच्चें हैं, जिसमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। घर का सारा काम करवाते थे ताऊ-ताईः दोनों पति-पत्नी सुबह से काम पर जाते थे और घर का पूरा काम करने का दबाव पलक पर डालते थे। पलक स्कूल जाती थी और घर पर होमवर्क करती थी। ऐसे में कई बार वह जब घर के काम नहीं कर पाती थी, तो दोनों उसे मारते थे। यह प्रताड़ना वे युवती को बीते दो सालों से दे रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी की थी।

विशाल कलश यात्रा के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ

भोपाल, नप्र। भोपाल में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ 6 नवंबर सुबह 11:00 से विशाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा गंगेश्वर महादेव मंदिर से कथा स्थल बैडमिंटन पार्क तिरुपति अभिनव होम्स पर पहुंची विधि विधान पूजा अर्चना के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ यह कथा 13 नवंबर तक चलेगी यह जानकारी मुख्य आयोजन कर्ता डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी राष्ट्रीय सचिव मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण आर्गनाइजेशन ने बताया कि 7 तारीख को सुखदेव आगमन वराह अवतार एवं धूव चरित्र एवं 8 तारीख को सती चरित्र प्रहलाद चरित्र एवं वामन अवतार 9 तारीख को श्री कृष्ण जन्म एवं नंद महोत्सव 10 तारीख को श्री कृष्णा बाल लीला गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग 11 तारीख को श्री कृष्ण

रासलीला उद्धव चरित्र एवं रुक्मणी विवाह 12 तारीख मंगलवार कथा 10 बजे से 2बजे सम्पन्न होगी जिसमें सुदामा चरित्र परीक्षित मौक्ष सुकदेव विदाई एवं व्यास पूजन एवं सायंकाल 4 बजे तुलसी माता और शालिग्राम की बारात गंगेश्वर महादेव मंदिर से निकली जायेगी जायेगी एवं 13 तारीख को हवन पूर्णाहुति एवं भंडारा दोपहर 1:00 बजे से संपन्न होगा। मुख यजमान श्रीकांत अवस्थी जी ने बताया की कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य पंडित श्री मधुसूदन शास्त्री मधुर के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होंगा सभी भक्तजन प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म का लाभ लें निवेदक तिरुपति अभिनव होम्स एवं बालाजी परिवार अयोध्या बायपास भोपाल इस अवसर पर पंडित गिरीश शर्मा वरिष्ठ समाज सेवी रामबाबू शर्मा राकेश चतुर्वेदी अरुण भैया कृष्णा भैया एवं तिरुपति कॉलोनी के अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष एवं सभी कॉलोनी वासी सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित थे।

अवमानना तो हो चुकी न्यायालय सीधे दंड की व्यवस्था करेगा क्या: शिव मोहन सिंह

भोपाल। सोशल मीडिया पर आज जागरूकता को लेकर आई पोस्ट बुद्धी जीवियों को तो झकझोर रही है आम जन मानस में यह पोस्ट कितना प्रभाव डाल रही कहा नहीं जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर जागरूकता की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए जिसमें छूट जाने वाले या खबरों में नजर अंदाज़ किए गए मुद्दे उभर जाते.. शिव मोहन सिंह किसान संगठन से जुड़े एक गंभीर पदाधिकारी है जो समय समय पर सोशल मीडिया में झकझोर देने वाली टिप्पणी पोस्ट कर सजग कर देते जैसे आज उन्होंने आज वयोवृद्ध डीन को अतिरिक्त पेंशन भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अरुण श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगने को लेकर बेवाक लिखा। श्री सिंह अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि आए दिन इस प्रकार के प्रकरण देखने और सुनने में आते हैं। जिसमें पीड़ित जैसे तैसे धन की व्यवस्था कर वकील की व्यवस्था करते हैं इसके बाद अनेक दिनों तक न्याय की आशा में आस लगाए बैठे रहते हैं। जब उनको न्याय मिल जाता है और वह खुशी-खुशी घर वापस आ जाते हैं, लेकिन वही पुरानी यंत्रणा फिर से प्रारंभ होती है। क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश को बगैर कारण प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानते और पीड़ित को फिर उसी न्याय को प्राप्त करने के लिए उसी न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसा क्यों यह समझ से परे है पीड़ित को फिर वही एक लंबी प्रक्रिया का फिर सामना करना पड़ता है..?

न्यायालय के आदेश का पालन करवाने वाले सरकारी अधिकारियों को कोर्ट थोड़ी बहुत झिड़की सुनाकर कोर्ट के आदेश की पालना का निर्देश देते हैं अधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन भी सुनिश्चित कर देते हैं यह समझ से परे है पीड़ित को कितनी कठिनाइयों के बाद न्याय मिल पाता है। सभी जानते हैं न्याय पाने के लिए छोटे शहरों से जबलपुर अथवा इंदौर ग्वालियर की हाई कोर्ट पीठ तक आम आदमी के लिए पहुंच पाना कितना मुश्किल है जबकि अवमानना करने वाले अधिकारी पूरे सरकारी संसाधन का सदुपयोग करते हुए नियत दिन एवं समय पर पेशी पर पहुंच जाते.. जबकि भारी मशक्कतों के साथ मुकदमा जीतने के बाद पीड़ित को ऐसा महसूस होता है जैसे सांप सीढ़ी के खेल में 99 पर पहुंचने के बाद सांप काट खाता है और वह एक की संख्या पर आ जाता है. तो क्या ऐसा मान लिया जाए सरकार का न्याय विभाग जानबूझकर आम नागरिकों को उनके अधिकारों को दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का परिचय नहीं दे रहा..? या माननीय न्यायालय भारत सरकार के न्याय विभाग के आगे दोयम दर्जे की साबित हो रही..देश में मुकदमों के बोझ से लदी अदालतें अनावश्यक अवमानना के ऐसे अनेक प्रकरण एडिशनल के रूप में उस बोझ को ढोने के लिए अभिशप्त क्यों हैं. अब समय आ गया है भारत सरकार के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आपसी समन्वय बनाकर इस बाबत कोई ना कोई कदम उठाना होगा ताकि न्यायालय के आदेश के साथ ही उसकी कंप्लायंस ना होने की दशा में उस आदेश के साथ ही अवमानना की कार्रवाई पीड़ित व्यक्ति द्वारा माननीय न्यायालय को आदेश की प्रति के साथ प्रेषित सिर्फ शपथ पत्र के साथ रजिस्टर्ड सूचना पत्र के साथ क्यों ना प्रारंभ कर मामले को रफा दफा किया जाए..? इस प्रकार के कदम उठाए जाने से जहां आम पीड़ित नागरिक को सुलभ न्याय तो मिलेगा ही वही भारत में मुकदमों की बोझ से दबी हुई न्यायालयों को भी राहत मिलेगी. श्री सिंह आगे लिखते हैं कि जब आप और हम सभी जानते हैं बहुत लंबी चली बहस और मुसाहबो के बाद या आम भाषा में कहें तो सात छलनी में छनने के बाद उच्च न्यायालय से निर्णय बाहर निकल कर आता है। फिर माननीय न्यायालय की अवमानना किया जाना स्वयंमेव आपराधिक षड्यंत्र की सीमा में अपने आप आ जाता... क्या माननीय न्यायालय को आदेश पारित करने के साथ ही सिर्फ एक लाइन का उस आदेश में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं यदि आदेश का पालन नहीं हुआ। और माननीय न्यायालय उचित समझे कि पीड़ित की फरियाद यदि इस न्यायालय को पुनः प्राप्त हुई तो इसे अवमानना मानते हुए कोर्ट अपना निर्णय सख्त आदेश के साथ संबंधित के विरुद्ध पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा...?

इससे यह होगा आम नागरिक (जबकि संबंधित प्रकरण में तो वह आम नहीं खास नागरिक है क्योंकि वह सीनियर सिटीजन है और उसके अधिकारों की रक्षा करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है) प्रशासनिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होकर उसे सर्व सुलभ न्याय तुरंत प्राप्त होगा और कोर्ट पर बढ़ रहे मुकदमों का वजन कम होगा इसके साथ ही देश की न्याय प्रणाली जो लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में जानी जाती है उस पर आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

चाकू मारकर नाबालिग की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। स्कूटी से आए तीन लोगों ने एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर भी नाबालिग हैं। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना गंज थाना इलाके के शंकर नगर में बुधवार रात की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब एक बजे हुई इस वारदात में माचना नगर निवासी 17 वर्षीय नाबालिग लक्ष्य की हत्या हुई है। नाबालिग अपने साथियों के साथ मंदिर के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान स्कूटी से आए राजेश वाडिवा उर्फ लड्डू (27) के साथ आए दो नाबालिगों में से एक ने लक्ष्य से झगड़ा शुरू कर दिया। इस बीच एक नाबालिग ने चाकू निकालकर उसके पेट में दो और कमर में एक वार किया। इससे लक्ष्य गंभीर रूप से घायल हो गया। लक्ष्य को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद लक्ष्य के साथियों ने नाबालिग आरोपी को मौके पर ही जमकर पीटा। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से फरार लड्डू और एक अन्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। गंज टीआई रविकांत डेहरिया ने बताया कि लक्ष्य के साथ एक अन्य नाबालिग का पिछले गणेश विसर्जन के दौरान झगड़ा हुआ था। इसके अलावा भी उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। यही हत्या की वजह बनी। मृतक नाबालिग पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाता था। जबकि आरोपी भी केटरिंग का काम करते हैं।

सतना में सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, बगहा में हुआ हादसा

सतना (नप्र)। सतना के बगहा के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सतना जिले के जैतवारा थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल विजय लाडिया बुधवार की रात में अपनी बाइक से जैतवारा से सतना किसी काम से आ रहे थे। रात लगभग 9 बजे शहर के बगहा स्थित लवडेल स्कूल के पास लाल रंग की तेज रफ्तार पजेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही विजय सड़क पर गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हेड कांस्टेबल को सतना जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चैकअप के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया

एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे: हादसे की सूचना मिलते ही एसपी आशुतोष गुप्ता, सीएसपी महेंद्र सिंह, टीआई कोतवाली रावेंद्र द्विवेदी, टीआई सिविल लाइन योगेंद्र सिंह, समेत तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे। जैतवारा थाना प्रभारी भी खबर मिलने पर अस्पताल पहुंचे। शव को पोस्टमॉर्ट्म के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। जहां कल पोस्टमॉर्ट्म कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

डेढ़ महीने में दूसरे पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत: गौरतलब है कि सतना शहर में सड़क हादसे में पिछले डेढ़ महीने के दौरान पुलिस कर्मी की मौत का यह दूसरा मामला है। इसके पहले नवरात्रि के दौरान नए फ्लाई ओवर पर हुए हादसे में प्रधान आरक्षक संतोष कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिनकी पिछले हफ्ते इलाज के दौरान मौत हो गई।

मुरम के गड्ढे में मिला ग्रामीण का शव

परिजनों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पर लगाए हत्या के आरोप, थाने के बाहर शव रखकर लगाया जाम

शिवपुरी (नप्र)। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र के तेहरी गांव के रहने वाले ग्रामीण का शव महुआ गांव के पास मुरम के गड्ढे में गुरुवार की सुबह पड़ा हुआ मिला। ग्रामीण बुधवार शाम से लापता हो गया था। परिजनों ने मायापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित उसके परिजनों पर हत्या करने के आरोप लगाते हुए शव को मायापुर थाना के बाहर रख कर रऩ्नौद-पिछोर मार्ग को जाम कर दिया। बता दें कि गुरुवार सुबह 9 बजे से लगाया गया, जाम 4 बजे के बाद भी लगा हुआ है। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। कई वाहनों को वापस लौटना पड़ रहा है।

बुधवार की रात से था लापता

परिजनों के मुताबिक, 48 वर्षीय बुन्देल सिंह यादव बुधवार की शाम अपने खेत से मजदूर करने के लिए बाइक पर सवार होकर निकला था। लेकिन वह रात में वापस नहीं लौटा था। देर रात से परिजनों ने बुन्देल सिंह की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। गुरुवार सुबह महुआ गांव के पास सड़क पर बुन्देल सिंह की बाइक रखी मिली। यहां से कुछ दूरी पर मुरम के एक गडढे में बुन्देल सिंह मृत अवस्था में मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके बाद परिजन बुन्देल के शव को मायापुर थाना लेकर पहुंचे। यहां उन्होंने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है।

मंदिर हटाने पहुंचे तहसीलदार,टीआई को लौटना पड़ा

मूर्ति के सामने बैठे लोग; रामधुन बजाई, हनुमान चालीसा का पाठ किया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अयोध्या एक्सटेंशन में गुरुवार को मंदिर हटाने को लेकर हंगामा हो गया। तहसीलदार और थाना प्रभारी कार्रवाई करने पहुंचे थे। तभी सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और मूर्ति के सामने ही धरने पर बैठ गए। रामधुन गाई और हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोगों के इस विरोध के बाद अधिकारियों को लौटना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ भाजपा पार्षद छाया ठाकुर ने भी मंदिर को तोड़ने का विरोध किया। अयोध्या एक्सटेंशन इलाके के शंकर गार्डन मोहल्ले में एक पार्क है, जहाँ गणेशोत्सव के दौरान पार्क के एक हिस्से में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। मंदिर को हटाने के लिए कलेक्टर और एसडीएम से शिकायत की गई थी। गुरुवार को गोविंदपुरा तहसीलदार दिलीप चौरसिया, अयोध्या नगर थाना प्रभारी महेश लिल्हारे, राजस्व निरीक्षक मायाराम यादव पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और पार्षद ने भी मंदिर हटाने को लेकर विरोध जताया।

जेसीबी के सामने पहुंचे, धरने पर बैठे: मंदिर को हटाने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और जेसीबी के सामने पहुँच गए। इसके बाद मंदिर परिसर में जाकर मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में एमआईसी सदस्य और क्षेत्र की पार्षद छाया ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारी-कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उन्होंने भी मंदिर को हटाने या तोड़ने का विरोध किया। करीब एक घंटे तक रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अफसर वापस लौट गए।

आसामाजिक तत्वों का डेरा रहता था

विहिप के जिला सह मंत्री उपेंद्र शर्मा ने बताया कि पार्क में पहले से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहे हैं। चूंकि यहां असामाजिक तत्वों का डेरा भी रहता है, इसलिए मोहल्ले के लोगों ने हनुमान भगवान की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की। वे नियमित रूप से पूजा-अर्चना करने आते हैं और मंदिर को हटाने का विरोध करते हैं। इस मामले में मंत्री, सांसद, और विधायकों से भी शिकायत करेंगे। मंदिर हटाने की सूचना मिलते ही एमआईसी मेंबर और पार्षद छाया ठाकुर भी मौके पर पहुंचीं।

शिकायत करने वाले नहीं पहुंचे

तहसीलदार चौरसिया ने बताया कि मंदिर को लेकर शिकायत की गई थी और उसी पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। मौके पर शिकायत करने वालों का इंतजार किया गया, लेकिन वे नहीं आए। दोनों पक्षों को एसडीएम रवीश श्रीवास्तव के सामने शुक्रवार को बुलाया गया है।

अब डिजिटल बोर्ड से पढ़ेंगे 'आदिवासी' छात्र

विकासखंड मुख्यालय में खुलेगी ई-लाइब्रेरी; बनेंगे पीवीटीजी हॉस्टल

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में आदिवासी समाज के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए अब एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित विशिष्ट श्रेणी के इन शिक्षण संस्थाओं में कक्षा में डिजिटल बोर्ड लगाये जाएंगे, इसके लिये विभाग द्वारा तेजी से कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा सभी आदिवासी विकास खंड मुख्यालय में ई लाइब्रेरी भी खोलने की तैयारी है।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया: सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में डिजिटल बोर्ड लगाने के लिये 'केपिटल मद' से बोर्ड खरीदने एवं उसे लगवाने का काम किया जा रहा है, इसी प्रकार सभी विभागीय कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालयों में भी डिजिटल बोर्ड लगाये जायेंगे। इसके लिये बजट की राशि प्रावधान बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है।

आदिवासी विकासखंड में ई-लाइब्रेरी की तैयारी: जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकास खंड मुख्यालय में ई-लाइब्रेरी भी प्रारंभ की जायेंगी। इसके लिये ई-लाइब्रेरी की क्रियान्वयन, रूपरेखा एवं उपकरण स्थापना के लिये आवश्यकतानुसार धनराशि का मांग प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। राज्य शासन से प्रस्ताव अनुमति एवं बजट आवंटन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

पीवीटीजी छात्रावास भवन बनाये जाएंगे: जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि प्रदेश में बैगा, भारिया, सहरिया तीन विशेष रूप से कमजोर एवं पिछड़ी जनजातियां (पीवीटीजी) निवास करती हैं। इन जनजातियों के विद्यार्थियों को संभागीय मुख्यालय में रहकर पढ़ने की सुविधा प्रदान करने के लिये विभाग द्वारा पीवीटीजी छात्रावास भवन बनाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जबलपुर एवं ग्वालियर में यह छात्रावास भवन बनाये जायेंगे। इसके बाद ऐसा ही एक पीवीटीजी छात्रावास भवन शहडोल संभागीय मुख्यालय में भी बनाने पर विचार किया जा रहा है।

टीचर ने छात्रों के बैग को बनाया तकिया

स्कूल में शर्ट उतारकर सोते हुए टीचर का वीडियो वायरल, बीईओ ने दिए जांच के आदेश

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के मझौली तहसील स्थित प्राथमिक शाला नंदग्राम में पदस्थ एक टीचर का वीडियो सामने आया है। वीडियो में टीचर बच्चों के बैग पर सिर और पैर रखकर सोते हुए नजर आ रहे हैं। टीचर का नाम विनोद मांझी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा अधिकारी ने टीचर विनोद मांझी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि वीडियो के संबंध में टीचर मांझी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह सो गया था। बीईओ का कहना है कि इससे पहले भी विनोद मांझी के खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं।

बच्चों को खेलने के लिए कहा और टीचर सो गया: जानकारी के मुताबिक, विनोद मांझी प्राथमिक शाला नंदग्राम में पदस्थ हैं। बुधवार को स्कूल आए टीचर मांझी ने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें खेलने के लिए कहा और खुद कक्षा में आराम करने लगे। विनोद ने अपनी शर्ट उतारकर छात्रों के स्कूली बैग को सिर के नीचे तकिए की तरह रखा, इतना ही नहीं, कुछ बैग उनके पैरों के पास भी रखे थे। बच्चों ने विनोद मांझी की इस हरकत के बारे में गांव के कुछ लोगों को बताया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शिक्षक का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्कूल में शिक्षक के सोते हुए वीडियो को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी बयान सामने आया है।

बीईओ ने जांच के लिए टीम गठित की: ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अतुल चौधरी का कहना है कि इससे पहले भी विनोद मांझी के खिलाफ बच्चों के साथ मारपीट करने और उन्हें न पढ़ाने संबंधी शिकायतें मिली हैं। अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बच्चों के बैग पर सिर रखकर सोते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज ही स्कूल का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें विनोद मांझी को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया था, जिस पर उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही है। बीईओ ने बताया कि इस मामले में एक जांच टीम बनाई गई है, और रिपोर्ट आते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

गुड गवर्नेंस के लिए नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसिस को मिलेगा मंच

- **कलेक्टरों से सरकार ने मांगी नवाचार की थीम, बैकग्राउंड और रिजल्ट की रिपोर्ट**

भोपाल (नप्र)। गुड गवर्नेंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसिस को बढ़ावा देने और ऐसा करने वाले अफसरों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही संगोष्ठी करेगी। नीति आयोग के निर्देश पर नवाचार को बढ़ावा देने राज्य सरकार ने इसके लिए कलेक्टरों को पत्र लिखा है। जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। नवाचार को आउटकम, रिप्लीकेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के आधार पर चुना जाएगा। इसके बाद चुने गए जिलों के कलेक्टर या उनके जिलों के उप सचिव स्तर तक के अधिकारी को संगोष्ठी में प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा या बेस्ट प्रैक्टिसिस का प्रकाशन किया जाएगा।

प्रमुख सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग संजय कुमार शुक्ल ने कलेक्टर्स को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है-सुशासन और नए सफल प्रैक्टिसिस की पहचान करना राज्य नीति आयोग की जिम्मेदारी है। इसलिए सफल गवर्नेंस मॉडल के लिए नीतिगत सुझाव देने और प्रदेश में कुशल नागरिक सेवा को सुलभ बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना आयोग का दायित्व है। इसी के चलते जिलों में किए जा रहे अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा जिलों की बेस्ट प्रैक्टिसिस को प्रदेश भर में पहुंचाने के लिए जिला अधिकारियों को जिला स्तर की बेस्ट प्रैक्टिसिस और नवाचारों के लिए मंच दिया जाना है।

नीति आयोग दे रहा मंच

प्रमुख सचिव ने कहा कि जिले में हो रहे नवाचार और बेस्ट प्रैक्टिसिस को प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग के निर्देश के अनुसार आवेदन किए जाएं। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग जिलों के नवाचार और बेस्ट प्रैक्टिसिस को प्रोत्साहित करने एक मंच प्रदान कर रहा है। इसके लिए विषयवार संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है। सुशासन एवं अभिनव सफल प्रथाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की पहचान करना राज्य नीति आयोग का प्रमुख कार्य है।

इस आधार पर होगा चयन

प्रमुख सचिव शुक्ल ने कहा है कि आयोग द्वारा जिलों से प्राप्त आवेदनों को उनके नवाचार के आउटकम, रिप्लीकेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के आधार पर चयनित किया जाएगा। चुने गए जिलों के कलेक्टर या उनके जिलों के उप सचिव स्तर तक के अधिकारी को संगोष्ठी में प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा या बेस्ट प्रैक्टिसिस का प्रकाशन किया जाएगा।

शिवराज को प्रचार के लिए नहीं मिला हेलिकॉप्टर

उपनेता प्रतिपक्ष कटारे बोले- बड़े नेता जानबूझकर कर रहे अपमान; बुधनी की जनता सहेगी नहीं

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार (7 नवंबर) को बुधनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। शिवराज को हेलिकॉप्टर से यहां जाना था। ऐन वक्त पर उन्हें हेलिकॉप्टर नहीं मिल सका, वे कार से पहुंचे। इसे लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने वीडियो जारी कर बीजेपी के बड़े नेताओं पर शिवराज को अपमानित करने का आरोप लगाया है। कटारे ने कहा- बीजेपी अपने सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान को अपमानित कर रही है। उन्हें हेलिकॉप्टर से जाना था, लेकिन उन्हें हेलिकॉप्टर नहीं दिया गया।

शिवराज मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता: कटारे ने कहा- आज मध्य प्रदेश भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान का बुधनी उपचुनाव को लेकर हेलिकॉप्टर से दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित था। मैंने दौरा कार्यक्रम देखा, उसमें हेलिकॉप्टर से जाना था, लेकिन जैसे ही बीजेपी के बड़े नेताओं और राज्य सरकार को ये पता चला तो अपमानित करने के लिए उनसे हेलिकॉप्टर छीन लिया गया। जिसके चलते आनन-फानन में पूरा कार्यक्रम शिवराज सिंह चौहान ने कार से बनाया।

शिवराज के फेस पर चुनाव, पर सीएम नहीं बनाया: उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा- आज प्रदेश में भाजपा की सरकार उन्हीं की देन है। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद पहले तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद जब बुधनी में उपचुनाव की बारी आई तो उनके बेटे को टिकट भी नहीं दिया गया। अब उनसे हेलिकॉप्टर भी छीन लिया गया है। बुधनी की जनता अपने नेता का कितना अपमान सहेगी।

मालेगांव ब्लास्ट केस-प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट का वारंट

पूर्व सांसद ने एक्स पर लिखा-कांग्रेस का टॉर्चर मृत्युदायी कष्ट; जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी

भोपाल (नप्र)। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने यह फोटो एक्स पर शेयर की है जिसमें उनके चेहरे पर सूजन दिख रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने उन्हें वारंट जारी किया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट का वारंट जारी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। तस्वीर में प्रज्ञा के चेहरे पर काफी सूजन नजर आ रही है। इस पर उन्होंने कहा- कांग्रेस के टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए। प्रज्ञा ठाकुर के करीबियों ने बताया कि पूर्व सांसद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके चेहरे पर सूजन है। उन्हें देखने में भी दिक्कत आ रही है।

प्रज्ञा ठाकुर ने एक्स पर अपनी ये तस्वीर शेयर की: प्रज्ञा ठाकुर ने लिखा- दवाओं से पूरे शरीर में सूजन है। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा।

मालेगांव केस में एनआईए कोर्ट ने जारी किया है वारंट: दरअसल, एनआईए कोर्ट ने मंगलवार (6 नवंबर) को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10 हजार का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही उन्हें 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। इससे पहले प्रज्ञा को मुंबई में ही रहकर इलाज कराने और पेशी पर हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश दिया था।

मार्च में भी जारी हुआ था प्रज्ञा के खिलाफ वारंट

इससे पहले मार्च में भी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ था। अब एक बार फिर कोर्ट ने उनके खिलाफ 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। अंतिम तारीख 13 नवंबर है। इसका मतलब ये है कि उन्हें 13 नवंबर तक कोर्ट के सामने पेश होना होगा।

सात आरोपियों के खिलाफ चल रहा है केस

मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा है। इन आरोपियों में भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत ले.कर्नल (रिटायर्ड) प्रसाद पुरोहित, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी का नाम शामिल है।

मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं प्रज्ञा ठाकुर: भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

एनआईए कोर्ट में दिया था खराब सेहत का हवाला: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खराब सेहत की वजह से पिछले काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहीं थी। इसको लेकर उनके वकील जेपी मिश्रा ने कोर्ट से पेशी में छूट देने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब मामले में अंतिम बहस चल रही है और इस दौरान उनका हाजिर रहना अनिवार्य है।